

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» एंज्वायडिड गाउन में खुद को बॉलीवुड ..



चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा रद्द किया, पाक मंसूबे नाकाम!



नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) से पीओके क्षेत्रों में चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा रद्द करने को कहा है। पीसीबी ने गुरुवार (14 नवंबर) को कहा था कि ट्रॉफी स्काई, हुंजा, मरी और मुजफ्फराबाद का दौरा करेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई ने पीसीबी की योजना पर आपत्ति जताई और फिर आईसीसी ने पाकिस्तान बोर्ड से उक्त शहरों में ट्रॉफी का दौरा रद्द करने को कहा। सूत्रों के अनुसार, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी ट्रॉफी को पीओके ले जाने के पीसीबी के कदम की निंदा की।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने स्काई, मरी और मुजफ्फराबाद में 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के नियोजित ट्रॉफी दौरों को रद्द कर दिया है, ये क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आते हैं। यह निर्णय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) द्वारा इन शहरों को दौरों के कार्यक्रम में शामिल करने की घोषणा के तुरंत बाद आया, जिस पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने तत्काल आपत्ति जताई थी। उल्लेखनीय है कि पीसीबी ने 16 से 24 नवंबर तक चैंपियंस ट्रॉफी के राष्ट्रव्यापी

दौरों की घोषणा की थी। आठ टीमों का यह टूर्नामेंट फरवरी-मार्च 2025 में पाकिस्तान में आयोजित किया जाना है और क्रिकेट के इस महाकुंभ की तैयारी के लिए पीसीबी ने ट्रॉफी दौरों का आयोजन किया था। हालांकि, इंडिया टुडे को पता चला है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की विवादित भूमि के अंतर्गत आने वाले शहरों में ट्रॉफी दौरों को रद्द कर दिया गया है।

चैंपियंस ट्रॉफी विवादों में

इस बीच, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विवादों में घिर गई है, क्योंकि भारत ने इस क्रिकेट इवेंट के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आईसीसी को पत्र लिखकर टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाने से भारत के इनकार पर स्पष्टीकरण मांगा है। आईसीसी को लिखे अपने पत्र में पीसीबी ने भारत के रुख के बारे में आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगा है। पाकिस्तान की ओर से भेजे गए पत्र में इवेंट के प्रारूप या संभावित हाइब्रिड मॉडल पर चर्चा नहीं की गई है।

हालांकि, आईसीसी द्वारा पीओके क्षेत्रों में ट्रॉफी दौर रद्द करने के बाद, पीसीबी को अब एक नई योजना बनानी होगी।

पीसीबी ने किया था ऐलान

पीसीबी ने गुरुवार शाम को एकस पर लिखा, तैयार हो जाओ, पाकिस्तान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ट्रॉफी टूर 16 नवंबर को इस्लामाबाद में शुरू होगा, जिसमें स्काई, मरी, हुंजा और मुजफ्फराबाद जैसे दर्शनीय पर्यटन स्थलों का भी दौरा किया जाएगा। ट्रॉफी टूर 16 से 24 नवंबर तक चलेगा और ट्रॉफी 14 नवंबर (गुरुवार) को इस्लामाबाद पहुंचेगी।

विशेष रूप से, यह टूर उन तीन शहरों में नहीं होगा, जिन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के मैचों की मेजबानी करने की योजना है। लाहौर, कराची और रावलपिंडी - ये तीन स्थान खेलों की मेजबानी करेंगे।

हालांकि, मौजूदा धुंध के कारण ट्रॉफी इन शहरों से दूर रहेगी। यह देखना बाकी है कि क्या पीसीबी अब इन स्थानों पर ट्रॉफी न ले जाने की अपनी पिछली योजना में कोई बदलाव करता है। पीसीबी द्वारा आईसीसी से बीसीसीआई से पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार करने के लिए स्पष्टीकरण मांगने के बाद से कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है।

कई रिपोर्टों में कहा गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल की संभावना है जिसमें भारत अपने मैच यूएई या श्रीलंका में खेलेगा। हालांकि, आईसीसी की ओर से अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। दिलचस्प बात यह है कि आईसीसी 11 नवंबर को 100 दिन की उलटी गिनती तय करके प्रतियोगिता का कार्यक्रम घोषित करने वाला था।

सीओपी29 में प्रतिबंधात्मक उपाय भेदभाव

जलवायु परिवर्तन के नाम पर कार्रवाई का भारत ने जताया विरोध

कुमार विवेक

जलवायु परिवर्तन के नाम पर एकरतफा कार्रवाई भेदभावपूर्ण है, बहुपक्षीय सहयोग को नुकसान पहुंचाते हैं और ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। भारत ने शुक्रवार को यह बात कही। बाकू में आयोजित सीओपी29 में एकरतफा उपायों पर अध्यक्षीय परामर्श में हस्तक्षेप करते हुए भारत ने कहा कि यह वैश्विक चिंता का विषय है, जिस पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकासशील देशों के विकास के मार्ग बाधित न हों।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में 130 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े समूह जी-77 तथा समान विचारधारा वाले विकासशील देशों सहित विकासशील देशों के अन्य समूहों ने भी इस मुद्दे पर अपना कड़ा विरोध दर्ज करवाया। हालांकि, विकसित देशों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ ने तर्क दिया कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सही मंच नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन पहले ही विचार कर रहा है।

भारत ने कहा कि प्रतिबंधात्मक एकरतफा उपायों से विकासशील और निम्न आय वाले देशों को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन की लागत वहन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे विकसित देशों की जलवायु वित्त प्रतिक्रियाएं कमजोर होती हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से औद्योगीकरण से लाभ मिला है और जिन्होंने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान दिया है। भारत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से बचाव की कार्रवाई के नाम

पर कोई भी एकरतफा उपाय विकासशील देशों के प्रति भेदभावपूर्ण और बहुपक्षीय सहयोग के लिए हानिकारक है। ये समानता के सिद्धांतों और सीबीडीआर-आरसी और यूएनएफसीसीसी प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। भारत ने आगे कहा कि एकरतफा व्यापार उपाय निर्यात की लागत बढ़ाकर निर्यात आधारित विकास के माध्यम से औद्योगीकरण करने के इच्छुक देशों के खिलाफ भेदभाव करते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि लक्ष्य वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, तो जलवायु नीतियों को रियायती वित्त की पेशकश करने और शमन व अनुकूलन दोनों को संबोधित करने के लिए देशों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

भारत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित व्यापार उपायों का सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों के संदर्भ में समतापूर्ण और न्यायसंगत बदलावों पर उनके संभावित प्रभाव के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यापार-संबंधी जलवायु नीति को न्यायसंगत और उचित परिवर्तन, सतत विकास और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव पर विचार करना चाहिए।

सोमवार को कॉप 29 के प्रारंभिक पूर्ण अधिवेशन में काफी देरी हुई, क्योंकि विकसित और विकासशील देश इस बात पर बहस कर रहे थे कि यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जैसे एकरतफा व्यापार उपायों को एजेंडा में शामिल किया जाए या नहीं। चीन ने BASIC समूह के देशों की ओर से पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र

जलवायु निकाय के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि इस वर्ष के शृङ्खल में एकरतफा व्यापार उपायों के मुद्दे पर ध्यान दिया जाए।

सीबीएएम यूरोपीय संघ द्वारा भारत और चीन जैसे देशों से आयातित ऊर्जा-गहन उत्पादों, जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक और एल्यूमीनियम पर प्रस्तावित कर है। यह कर इन वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन पर आधारित है। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही इस तंत्र के अपने संस्करणों को लागू करने के विभिन्न चरणों में हैं।

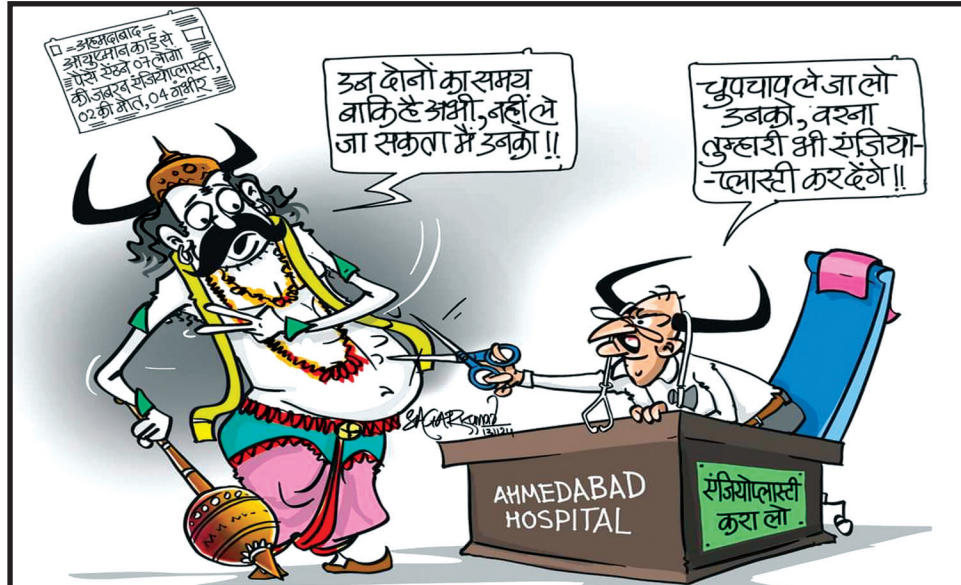
यूरोपीय संघ ने पहले तर्क दिया था कि यह तंत्र घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है, जिन्हें कठोर पर्यावरणीय मानकों का पालन करना होगा, तथा आयात से होने वाले उत्सर्जन को रोकने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने सीबीएएम को एकरतफा और मनमाना करार दिया था और कहा था कि इस तरह के उपायों से भारत के उद्योगों को नुकसान पहुंच सकता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संतुलन बिगड़ सकता है।

दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के अनुसार, सीबीएएम भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाले कार्बन-गहन वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत कर लगाएगा। यह कर भारत भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 0.05 प्रतिशत होगा।



प्रधानमंत्री मोदी वक्तव्य अधिनियम में करेंगे संशोधन: अमित शाह

मुंबई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्भव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेताओं के विरोध के बावजूद वक्तव्य अधिनियम में संशोधन करेंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के उमरखेड में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, %प्रधानमंत्री मोदी वक्तव्य बोर्ड कानून बदलना चाहते हैं, लेकिन उद्भव ठाकरे, शरद पवार और सुप्रिया सुले इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उद्भव जी, ध्यान से सुनिए, आप सभी जितना चाहें विरोध कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वक्तव्य अधिनियम में संशोधन करेंगे। अमित शाह ने कहा कि 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में दो खेमे हैं, एक पांडव जिसका प्रतिनिधित्व भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति कर रही है और दूसरा कौरव जिसका प्रतिनिधित्व महा विकास अघाड़ी कर रही है। उद्भव ठाकरे का दावा है कि उनकी शिवसेना असली है। क्या असली शिवसेना औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने के खिलाफ जा सकती है?



प्रमुख समाचार

छत्तीसगढ़ से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा होगा-शाह

चंद्रपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 31 मार्च, 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर देगी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "मोदी जी ने आतंकवाद और नक्सलवाद से देश को मुक्त करने के लिए काम किया है। उन्होंने देश को समृद्ध बनाते और दुनिया में इसका सम्मान बढ़ाने के लिए काम किया है।" शाह ने कहा, "छत्तीसगढ़ में जो भी बचा (नक्सल खतरा) है, हम उसे 31 मार्च 2026 तक समाप्त कर देंगे।" उन्होंने कहा, "मोदी जी ने महाराष्ट्र के विकास के लिए 15.10 लाख करोड़ रुपये भेजे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कई परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई है।" उन्होंने कहा कि यदि राज्य की जनता यहां महायुति की सरकार बनाती है तो महाराष्ट्र का गौरव फिर से बहाल हो जाएगा जो महा विकास अघाड़ी सरकार के दौरान खो गया था।

राम मंदिर को बम से उड़ा देंगे, धमकी के बाद सतर्कता बढ़ी

अयोध्या। यूपी के अयोध्या स्थित राम मंदिर को सिख फंरि जस्टिस चीफ खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसे लेकर अयोध्या में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पन्नू ने पिछले दिनों एक वीडियो जारी कर 16-17 नवंबर को कहा था कि राममंदिर में हिंसा होगी। हम हिंदुत्व विचारधारा की जन्मस्थली अयोध्या की नींव हिला देंगे। शुक्रवार को राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा एजेंसियों के साथ एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे ने बैठक भी की। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा में पहले से ही सीआरपीएफ, एसएसएफ, पुलिस व पीएसपी के जवान तैनात हैं। इसके लिए पूरा परिसर सीसीटीवी, वॉच टॉवर, बूम बैरियर, स्कैनर आदि सुरक्षा के आधुनिक संसाधनों से लैस है। एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे ने बताया कि सभी सुरक्षा एजेंसियों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे मंदिर परिसर को निगरानी आधुनिक कैमरों से की जा रही है। सीआरपीएफ व एसएसएफ की टीम को विशेष रूप से मुस्तैद रहने को निर्देशित किया गया है।

गढ़चिरोली के विकास में बाधा है वन विभाग-गडकरी

गढ़चिरोली। केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नितिन गडकरी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब गढ़चिरोली महाराष्ट्र का सबसे समृद्ध क्षेत्र बन जाएगा। उन्होंने वन विभाग पर नक्सल प्रभावित जिले के विकास में बाधा उत्पन्न करने का आरोप भी लगाया। गडकरी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तहत प्रचार के दौरान कहा कि कई लौह अयस्क कंपनियों गढ़चिरोली में काम शुरू कर रही हैं और उन्होंने इन उपक्रमों में नौकरियों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने गढ़चिरोली जिले के आधी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी बी आर आंबेडकर द्वारा तैयार संविधान में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं देगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने भाजपा उम्मीदवार मिलिंद नरोटे (आधी सीट) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकापा) उम्मीदवार बाबाराव आत्राम (अहेरी निर्वाचन क्षेत्र) के लिए प्रचार कर रहे थे। गडकरी ने महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री (1995 से 1999) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इस जिले में किए गए

वीरता का प्रेरणा स्रोत है जनजातीय समुदाय-योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजातीय समाज की गौरवपूर्ण संस्कृति और उनकी मातृभूमि के प्रति अपार निष्ठा को सम्मान देते हुए भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 'जनजातीय गौरव दिवस' पर अंतरराष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव की शुरुआत की। यह उत्सव राज्य की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित संगीत नाटक अकादमी में 15 से 20 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत के 22 राज्यों के साथ-साथ स्तोवाकिया और वियतनाम से भी कलाकार भाग ले रहे हैं। एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समुदाय मातृभूमि के प्रति त्याग, निष्ठा और वीरता का प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज ने केवल भारत का मूल संप्रदाय है, बल्कि यह समुदाय मातृभूमि के प्रति उच्च भाव से प्रेरित होकर देश की सेवा में सदैव तत्पर रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश पर विदेशी सत्ता का शिकंजा था, तब भगवान बिरसा मुंडा ने अपने समुदाय के अधिकारों की रक्षा और स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया।

ईडी ने 'लॉटरी किंग' से 8.8 करोड़ रुपये जब्त किए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चेन्नई में रहने वाले 'लॉटरी किंग' सेंटियागो मार्टिन के कारपोरेट कार्यालय से शुक्रवार को 8.8 करोड़ रुपये जब्त किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मार्टिन राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा चंदा देने वालों में से एक था। उसने अब रद्द की जा चुकी चुनावी बॉण्ड योजना के तहत 1,300 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा दिया था। अधिकारियों ने कहा कि लॉटरी किंग के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामलों की जांच के तहत कई राज्यों में छापे मारे गए। यह कार्रवाई मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में ईडी को मार्टिन के खिलाफ विस्तृत जांच की अनुमति देने के बाद हुई है। इससे पहले तमिलनाडु पुलिस ने मार्टिन व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामले को बंद करने का फैसला लिया था और निचली अदालत ने पुलिस को इस याचिका को स्वीकार कर लिया था। अधिकारियों ने कहा कि मार्टिन, उसके दामाद आधव अर्जुन और सहयोगियों से जुड़े तमिलनाडु के चेन्नई व कोयंबटूर, हरियाणा के फरीदाबाद, पंजाब के लुधियाना और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कम से कम 20 परिसरों की व्यापक कार्रवाई के तहत तलाशी ली जा रही है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य में सही नहीं है किसान की लागत और श्रम का आकलन

अशोक बंग

हाल ही में केंद्र सरकार ने रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की है। वहीं, कार्यरत और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को साल भर में करीब सात फीसदी वेतन और पेंशन में वृद्धि दी गई है। साथ ही पदोन्नति पर अलग से वेतनवृद्धि मिलती है। लेकिन कृषि उपज के दाम यानी एमएसपी में बढ़ोतरी बहुत कम की गई है।

एमएसपी को समर्थन मूल्य कहना असल में बहकावा है। इसका उद्देश्य है कि बाजार में कृषि उपज के खरीद के दाम एमएसपी से नीचे न गिरें और अगर गिरते हैं, तो सरकार उन उपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदकर मूल्य गिरने न दे। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। समर्थन मूल्य सुनने में भले ही अच्छा लगता है, पर यह घोषित मूल्य धोखे से भरा

होता है, क्योंकि हकीकत पूरे लागत-खर्च पर आधारित ही नहीं है। इसे?बारीकी से समझना जरूरी है। फसल उगाने के लिए किसान को कई खर्च, निवेश और विनियोग करने पड़ते हैं। इनके तीन प्रकार हैं-किसान द्वारा नकद भुगतान किए जाने वाले पहले प्रकार को ए-2 खर्च कहा जाता है। शुरुआत से ही कुछ साल पहले तक भी सरकारें सिर्फ?ए-2 प्रकार के खर्च को ही लागत खर्च में गिनती रहीं, लेकिन ए-2 के अलावा ऐसे ही दूसरे बड़े खर्च भी हैं, जिन्हें अनदेखा किया जाता रहा है। इस दूसरे प्रकार में वे खर्च हैं, जिन्हें फसल के लिए किसान को निवेश करना पड़ता है। जैसे कि परिवार के श्रम, घर की गोबर खाद, घर से बिजुई, सिंचाई के लिए कुएं?का पानी, घर की बैलजोड़ी-इन सबको एफएल अर्थात फैमिली लेबर प्रकार कहा गया। हालांकि अब सरकार इस प्रकार के कुछ खर्चें शामिल करने लगी है। तीसरे प्रकार के खर्चें?में विभिन्न लागत, जमीन का सालाना किराया, मवेशी के बाड़े,



भंडारण के मकानात, औजारों का किराया अथवा घिसावट (अवमूल्यन), कार्यगत पूंजी की समूची राशि पर ब्याज, खेती का प्रबंधन करने के लिए प्रबंधक के नाते किसान के समय का पारिश्रमिक, खेती के लिए किए जाने वाले प्रवास का खर्च, दूसरों से खासकर, सरकारी दफतरो से खेती के विभिन्न काम और कागजात के लिए खर्चें और उनके एवज में दी जाने वाली रिश्त अलग है। विक्रय के लिए परिवहन समेत कई प्रकार

के खर्चें, खेती के लिए आवश्यक संपत्ति के लिए (भूमि सुधार, कुआं, बाड़, बांध, रास्ता आदि) लगाने वाले खर्चें, किसान के अपने कौशल विकास के खर्चें, खेती?के लिए दी जाने वाली भेंट, और फसलों की विफलता, विपदा और अकाल के कारण खेती में लगे हुए संपूर्ण खर्चें-पेसी सब प्रकार की वास्तविक परंतु अदृश्य मदों पर?लगे खर्चें शामिल कर ही सच्चे उत्पादन खर्च पर आधारित दाम तय किए जाने चाहिए। इसलिए सिर्फ ए-2 व एफएल को शामिल करते हुए, लेकिन तीसरे प्रकार के खर्च की सारी मदों को छोड़कर हिसाब आंकना सीधा?छलावा है। सच में?संपूर्ण सर्व-समावेशी लागत खर्च के अलावा आय के लिए उसके ऊपर 50 फीसदी जोड़कर किसान को दाम मिले, तो ही किसानों का उद्यम करने वाले

अनदाता किसान को कुछ आय मिलेगी। अनेक सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाओं, अर्थशास्त्रियों, शोधकर्ताओं और संगठनों ने हिसाब लगाकर सरकार को रिपोर्ट देते हुए साबित किया है कि सरकार उत्पादन खर्च का जो आंकड़ा दिखाती है, उसकी तुलना में वास्तविक उत्पादन लागत खर्च लगभग डेढ़ गुना होता है। एमएसपी में सिर्फ छह फसलों को ही शामिल किया?गया है। एमएसपी पर बढ़ोतरी दो से छह फीसदी की गई है, जबकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन-भत्ते में सात फीसदी वृद्धि की गई है। इससे सरकार का किसानों के साथ सौतेला व्यवहार समझ आता है।

वहीं कृषि क्षेत्र को मिलने वाली सहूलियतें, छूट, अनुदान आदि नाकाफी हैं। गैट एप्रोमेंट, डंकल प्रस्ताव के समय केंद्र सरकार ने लिखकर कबूला था कि भारत का खेती क्षेत्र 70 फीसदी नकारात्मक सब्सिडी का नुकसान बर्दाश्त करके देश को पाल-पोस रहा है। इसी तरह हाल में सरकारी कृषि-लागत व मूल्य-आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक गुलाटी द्वारा सरकार को सौंपे गए हिसाब के अनुसार, वर्ष 2000 से 2015 के बीच 5 वर्षों में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपये?का नुकसान हुआ। मोटे तौर पर प्रत्येक किसान प्रतिवर्ष पांच एकड़ खेती पर करीब 50 हजार रुपये का नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। इसके समाधान के लिए किसानों को छूट, सब्सिडी और माफ़ी जैसे खेरात नहीं चाहिए, बल्कि खेती में किसान के श्रम, प्रबंधन व?उद्यमशीलता का सही दाम चाहिए।?खेती विरोधी सारी जुल्मी नीतियों (आयात-निर्यात नीतियों के साथ सभी) को हटाकर न्यायपूर्ण व पोषक नीतियां बनें। कृषि का बजट बढ़ाना चाहिए। साथ ही जलवायु परिवर्तन का आसमानी जुल्म, बाजार व सरकारी नीतियों के सुलतानी जुल्म से सुरक्षा के लिए खेती की सर्वोत्तम तकनीकें और पद्धतियां अपनानी होंगी।

राजस्व अधिकारी समिति की बैठक करवाकर धान खरीदी के समस्याओं का करवाएं निराकरण: कमिश्नर

जगदलपुर। कमिश्नर जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष से विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों से कमिश्नर डोमन सिंह ने कहा कि धान खरीदी में सतत निरीक्षण सहित राजस्व अधिकारी के नेतृत्व में प्रत्येक शनिवार को समिति की बैठक करवाकर ग्रामीणों की धान खरीदी से संबंधित समस्याओं का निराकरण करवाएं। खरीदी केंद्रों में पीडीएस दुकानों से प्राप्त होने वाले बारदाना की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएं। साथ ही संवेदनशील खरीदी केंद्रों में एसडीएम के माध्यम से निगरानी रखें। उन्होंने शहर के कांजी हाऊस में घुमंतुक पशुधन को रखने की क्षमता बढ़ाने या नए कांजी हाऊस स्वीकृत करने के निर्देश दिए। कांजी हाऊस पशुओं हेतु चारा, नैपियर घास की और पैरा व्यवस्था करने कहा। साथ ही जिलों में सीएसआर-डीएमएफटी मद से काऊ कैचर की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता बताई। पशुधन विकास विभाग के द्वारा गौशाला या कांजी हाऊस में नैपियर घास उगाने की पहल किया जा सकता है। उन्होंने शासन के निर्देशानुसार जिलों में गौ अत्याचार के लिए जमीन चिह्नकन जल्द करने के लिए कहा। मुख्य सड़क मार्गों में दुर्घटनाजन्य क्षेत्र में कांजी हाऊस का नोटीफिकेशन जरूर करवाएं। साथ ही एनएमडीसी के टाउनशीप एरिया में पशुओं के



लिए गोठान बनाने के पहल करवाएं। रोड सेप्टी के तहत हेलमेट जागरूकता रैली, नियमों का पालन करने वालों को सम्मानित करने जैसे नवाचार करें। कमिश्नर डोमन सिंह ने सड़क दुर्घटना आवादा एवं घुमंतुक पशुओं के नियंत्रण, जिले में कितने नवीन कांजी हाऊस एवं कितने पशु रखने की क्षमता स्वीकृत किये गये हैं, जिले में नगरीय क्षेत्र में कितने नवीन काऊ कैचर स्वीकृत किये गये हैं, जिले में सड़क के किनारे पशुओं को रखने के लिए नरेगा से कितने स्थानों पर समतलीकरण के कार्य स्वीकृत किये गये हैं की जानकारी ली गई। इसके अलावा रोड सेप्टी के नियंत्रण पर कार्यवाही, सड़क पर आवास एवं घुमंतुक मवेशों से दुर्घटना को प्रभावी नियंत्रण के लिए तैयार किये गये कार्य योजना पर चर्चा किया।

इसके अलावा खरीफ फसल 2024 में धान खरीदी की तैयारी के तहत विगत वर्ष संवेदनशील धान उपार्जन केंद्रों में नियुक्त कर्मचारियों की शिकायत के आधार पर कर्मचारियों को बदले जाने की अद्यतन जानकारी और पीडीएस में उपलब्ध बारदानों की स्थिति का संज्ञान लिया। बैठक में बस्तर ओलम्पिक प्रतियोगिता वर्ष 2024 में आयोजित विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम के तहत पंजीयन के विरुद्ध भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या पर भी चर्चा किया गया। कमिश्नर श्री सिंह ने कहा कि धान कटाई के कारण कई जगहों पर खिलाड़ी खेल गतिविधि में कम शामिल हुए हैं, इस हेतु सीनियर वर्ग में खिलाड़ियों की सहभागिता अधिक से अधिक हो, इसके लिए प्रयास करें। इस अवसर पर कलेक्टर बस्तर हरिस एस, जिला पंचायत सीईओ सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने किया तीन धान खरीदी केंद्रों का किया औचक निरीक्षण

बस्तर जिले के कलेक्टर हरिस एस ने शुक्रवार को जगदलपुर विकासखंड के दो उपार्जन केंद्र मंगडु कचोरा, बुरंदवाडा सेमरा और बकावण्ड विकासखंड के एक खरीदी केंद्र छोटे देवड़ा का औचक निरीक्षण किए। इस दौरान कलेक्टर ने धान बेचने और टोकन कटवाने पहुंचे किसानों से फसल की पैदावार, गत वर्ष कितना धान का विक्रय किए के संबंध में चर्चा किए। उन्होंने नए-पुराने बारदाना की उपलब्धता, बारदाना की गुणवत्ता सहित माइश्वर मापक यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, विद्युत व्यवस्था, चौकोदार की व्यवस्था, सतत निगरानी हेतु सीसीटीवी की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा चेक लिस्ट के आधार संबंधित केंद्र के अधिकारियों से सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान टोकन कटवाने की कार्यवाही करवाकर टोकन भी प्रदान किए। खरीदी केंद्र में उपलब्ध बारदाना का भी उन्होंने अवलोकन किया। साथ ही किसानों द्वारा लाए धान की माइश्वर की भी अपने समक्ष जांच भी करवाई और बोरा में भरे धान की इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन में माप करवाई। इस अवसर पर खाद्य अधिकारी राठौर, सीसीबी के रजा, डीएमओ श्री ध्रुव उपस्थित थे।

धान का अवैध परिवहन करते ट्रक जब्त कलेक्टर के निर्देश पर टीम ने की कार्रवाई

कबीरधाम। जिले में धान खरीदी शुरू हो गई है। खरीदी के दौरान अवैध धान खपाए जाने की संभावना बनी होती है। इसे देखते हुए कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देश पर जिले में धान के अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। धान के अवैध परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए बनाई गई संयुक्त टीम ने पंडरिया ब्लॉक के ग्राम रहमान कांथा स्थित लधुवोपनज नाका पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 314 क्विंटल धान का अवैध परिवहन करते ट्रक जब्त किया। वाहन क्रमांक सीजी 16 सी एल 1676 में 734 बोरी (314 क्विंटल) अवैध धान का परिवहन करना पाया गया। वाहन में मध्य प्रदेश से राजनांदगांव धान परिवहन किया जा रहा था। पूरा मामला अंतरराज्यीय धान परिवहन का है। धान की संपूर्ण मात्रा ट्रक में लोड सहित आगामी आदेश पर्यंत तक मंडी परिसर कृषि उपाज मंडी पंडरिया जिला कबीरधाम की अतिरिक्त में रखा जाएगा। जिले के 94 धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की बोहनी हुई। पहले दिन 1189 किसानों को टोकन जारी किए गए, जिनसे 56,520 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है। राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। जिले के 90 सफित के माध्यम से 108 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की जाएगी। जिले में सात हजार 280 नए किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। इस प्रकार कबीरधाम जिले के एक लाख 24 हजार 787 किसानों ने एक लाख 24 हजार 411 हेक्टेयर एकबा में अपना धान का समर्थन मूल्य में विक्रय करने के लिए पंजीयन कराया है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की मान से एक एकड़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है।



ब्लॉक स्तरीय बस्तर ओलंपिक उसूर का भव्य समापन

विकासखंड के विजेताओं को अतिथियों ने किया पुरस्कृत

बीजापुर। बीजापुर में बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन विकासखंड स्तर पर किया गया। जिसमें विकासखंड उसूर में विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 11 से 14 नवम्बर तक आवापल्ली में आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ के खेल गतिविधियों को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने प्रतिभागियों को मंच प्रदान करने उनमें खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और खेल भावना का विकास करने हेतु बस्तर ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।



सम्मिलित ग्राम पंचायत उसूर, बासागुड़ा, आवापल्ली, सापेड़, गगनपल्ली, कोंडापल्ली, चिपुरभट्टी, मारुडबाका, नरसापुर, धरमारम, लिंगागिरी, नम्बी एवं गलगम के दूरस्थ अंचल से खिलाड़ी शामिल हुए। उन्होंने इस खेल प्रतियोगिता की तारीफ करते हुए इसे बेहतर आयोजन बताया।

प्रतियोगिता के परिणाम व्यक्तितगत खेल जूनियर बालिका वर्ग 100 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान दीपिका तेलम एकलव्य दुर्गागुड़ा, दूसरा स्थान नदिनी बुरका इलमोडी ने प्राप्त किया। 200 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान सरिता पुनेम कोरसागुड़ा, दूसरा स्थान अपराजिता आवापल्ली ने प्राप्त किया। 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान सरिता पुनेम कोरसागुड़ा, द्वितीय स्थान सोनु पुजारी तिमपापुर ने प्राप्त किया। बालक जूनियर वर्ग 100 मीटर दौड़ में प्रथम

स्थान समीर कलमू, द्वितीय स्थान गोविंद कोरसा, 200 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान गोविंद कोरसा, द्वितीय स्थान राजेश अवलम ने प्राप्त किया। 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान सोनु कड़ती आवापल्ली ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान अरुण अंगनपल्ली गुटियाल ने प्राप्त किया।

कबड्डी प्रतियोगिता जूनियर बालिका वर्ग में प्रथम स्थान आवापल्ली एवं द्वितीय स्थान उसूर ने प्राप्त किया। सीनियर महिला वर्ग में प्रथम स्थान तिम्पापुर एवं द्वितीय स्थान इलमोडी ने प्राप्त किया। सीनियर पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान आवापल्ली एवं द्वितीय बासागुड़ा ने प्राप्त किया। जूनियर बालक वर्ग में प्रथम स्थान इलमोडी ने प्राप्त किया।

खो-खो प्रतियोगिता जूनियर बालिका वर्ग में प्रथम स्वामी आत्मानंद इलमिडी एवं द्वितीय स्थान आत्मानंद मुखीनार ने प्राप्त किया। जूनियर बालक वर्ग में प्रथम

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उसूर एवं द्वितीय स्वामी आत्मानंद इलमिडी ने प्राप्त किया। सीनियर पुरुष वर्ग में प्रथम आवापल्ली एवं द्वितीय मरुडबाका ने प्राप्त किया। सीनियर महिला वर्ग में प्रथम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उसूर एवं द्वितीय चेरामंगी ने प्राप्त किया।

रस्साकसी प्रतियोगिता सीनियर महिला वर्ग में प्रथम आवापल्ली एवं द्वितीय मरुडबाका ने प्राप्त किया। जूनियर बालिका वर्ग में प्रथम कस्तूरबा आवापल्ली एवं द्वितीय सेजेस आवापल्ली ने प्राप्त किया। सीनियर पुरुष वर्ग में प्रथम सेजेस उसूर एवं द्वितीय आवापल्ली ने प्राप्त किया। जूनियर बालक वर्ग में प्रथम पोटाकेबिन उसूर एवं द्वितीय सेजेस उसूर ने प्राप्त किया।

बॉलीबॉल प्रतियोगिता जूनियर बालक वर्ग में प्रथम तिम्पापुर एवं द्वितीय आवापल्ली ने प्राप्त किया। सीनियर पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान पुतकेल ने प्राप्त किया एवं द्वितीय स्थान मुंजाल कांकर ने प्राप्त किया। सीनियर महिला वर्ग में प्रथम स्थान इलमिडी एवं द्वितीय स्थान चेरामंगी ने प्राप्त किया।

सीएम साहब... बेटियां कैसे बनेंगी अफसर

छत्तीसगढ़ के सिकोसा गांव में नहीं खेल का मैदान, शराबियों से हैं परेशान

बालोद। बालोद जिले के ग्राम सिकोसा में आस पास के आधा दर्जन गांव के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शारीरिक तैयारी करने आते हैं। इन बच्चों का जन्मा देखते ही बनता है। रोजाना इन्हें शराबियों द्वारा किए गए गंदगी को साफ कर उसी जगह प्रैक्टिस करनी पड़नी है।

गांव में एक भी व्यवस्थित मैदान नहीं है तो ये निजी जमीनों को तैयारी के लायक बनाकर प्रैक्टिस करते हैं।

गांव के राजा बारले ने बताया कि ये जो संसाधन लगे हैं। जहां गांव और आसपास के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो सब मिलकर एकत्र किए गए पैसे से बनाए गए हैं, यदि सरकार पुरुष वर्ग में प्रथम सेजेस उसूर एवं द्वितीय आवापल्ली ने प्राप्त किया। जूनियर बालक वर्ग में प्रथम पोटाकेबिन उसूर एवं द्वितीय सेजेस उसूर ने प्राप्त किया।

उसके बाद वह एक व्यवस्थित माहौल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों की मांग है कि यदि उन्हें आसपास क्षेत्र में एक व्यवस्थित खेल मैदान दिया जाए तो वह बहुत कुछ कर



सकते हैं। बहुत आगे जा सकते हैं सरपंच का भी कहना है कि यदि प्रशासन और शासन चाहे तो गांव के बीचो-बीच एक गटन है। उसे मैदान के रूप में व्यवस्थित कर सकती है हमारे पास फंड की कमी है।

होमेश्वरी साहू ने बताया कि हम सब फरिस्ट गार्ड और जिला पुलिस बल की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए फिजिकल तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम सब यूनिटी बनाकर इस जगह पर एकत्र होते हैं और यह एक निजी जमीन है और हमारे पास कोई कोच भी नहीं है। हम स्वयं से मेहनत कर रहे हैं और यह सब लोहे से बने संसाधन जो मैदान में लगाए गए हैं। उसे सब को हमने आपस में थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठा कर लगाए हैं। मनीषा साहू, जागेश्वर प्रसाद और धर्मदर गायकवाड़ ने बताया कि बालोद जिला मुख्यालय या शहरों में तो व्यवस्थित मैदान है। मिखाने वाले कोच हैं। लेकिन यहां कुछ नहीं है फिर भी हम सब विभिन्न पदों पर जाना चाहते हैं। यहां ऊंची कूद के लिए बनाया गया। ये मैदान हमने तैयार किया है। पाइप लाकर लगाए हैं। यहां शारीरिक तैयारी करने के लिए पहुंचे हैं। हमें 400 मीटर दौड़ के लिए स्वतंत्र मैदान चाहिए जो व्यवस्थित भी हो। गांव के सरपंच आरोप चंद्रकार ने बताया कि हमने अपना कार्यकाल में कई बार लिखा है। शहर के बीचों बीच जो जगह है वो पर्याप्त है और यहां सरकार चाहे तो मैदान बना सकती है और शराबी जिस जगह को गंदा करते हैं वो निजी लगानी जमीन है। हम बच्चों को सुविधा देने निरंतर प्रयासत हैं।

तीन नर कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी, पुलिस जांच में जुटी



बलरामपुर रामनुजगंज। बलरामपुर रामनुजगंज जिला मुख्यालय से सटे ग्राम दहेजवार में बंद पड़े फ्लाई ऐश ब्रिक्स के पीछे खेत में तीन नर कंकाल मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर तत्काल बलरामपुर कोतवाली पुलिस पहुंची। जहां डॉग स्कॉयड एवं फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह ग्राम दहेजवार में बंद पड़े फ्लाई ऐश ब्रिक्स के पीछे नर कंकाल पड़ा था जिसको देखने के बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पूरा मामले की जांच में जुटी है।

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना संगठन के प्रमुख दिलीप मिरी जिलाबदर

कोरबा। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना संगठन के प्रमुख दिलीप मिरी पर कोरबा जिला कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। दिलीप मिरी को जिलाबदर कर दिया गया है। जिलाबदर की कार्रवाई से जुड़ा आदेश कोरबा कलेक्टर कार्यालय से जारी किया गया है। आदेश में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत इस न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 202404050400010 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 14/11/2024 अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि आप 24 घंटे के अन्दर जिला कोरबा तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सर्की, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्राढ़-चिरमिरी भरतपुर, गौरिला-पेण्ड्रा मरवाही जिले क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जावे और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति के इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश का तत्काल पालन किया जावे, पालन न करने पर आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसकी जानकारी संबंधित थानों को भेज दी गई है।

केंद्रीय विद्यालय चिरमिरी में बाल दिवस पर हुआ प्रतियोगिता

चिरमिरी। केंद्रीय विद्यालय चिरमिरी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का 135वां जन्मदिन बाल दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में विद्यालय के प्राचार्य पॉल उदय अरोंग द्वारा सरस्वती प्रतिमा एवं चाचा नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस मौके पर छोटे बच्चों के बीच फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन कराई गई। कार्यक्रम में छात्रों ने अपने रचनात्मक कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया। बच्चों ने पंडित नेहरू, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, रजिया सुल्तान, तीजन बाई, सावित्री बाई फुले और अन्य ऐतिहासिक पात्रों के रूप में प्रस्तुत होकर सबका दिल जीत लिया। बच्चों की मासूमियत और उनके रंग-बिरंगे परिधानों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्राचार्य एवं प्रभारी प्रधानाध्यापिका द्वारा पुरस्कृत किया गया।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में बाल मेले का आयोजन

चिरमिरी। बाल दिवस के अवसर पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय चिरमिरी में बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से भव्य बाल मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू के छाया चित्र पर दीपप्रज्वलन कर किया गया तदुपश्चात फीता काट कर विधिवत शुभारम्भ किया गया। बाल मेला के उद्घाटन अवसर पर भागवत प्रसाद देवसे सेवानिवृत्त प्राचार्य लाहिडी महाविद्यालय चिरमिरी, इन्दू पनेरीया अध्यक्ष एसएमडीसी, के उमरू रेड्डी पूर्व महापौर नगर पालिक निगम चिरमिरी, शिवांश जैन एसआईसी सदस्य, बलविंदर सिंह बी.ई.ओ, राकेश पराशर पार्षद, मुनमुन जैन अध्यक्ष लार्जंस क्लब वरदान चिरमिरी, राहुल भाई पटेल, मिथिलेश पराशर आदि गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। बच्चों ने उत्साहपूर्वक विभिन्न प्रकार की स्टॉल लगाये जिसमें मंचूरियन, समोसा, चाट, इडली, गुपचुप, दही बड़ा, पापड़ी चाट, मोमो, भेल, दही बडा, कटलेट, विभिन्न प्रकार के गेम आदि प्रमुख था। आयोजन में कुल 24 स्टॉल लगाये गये थे।

कुसमुंडा कोल परियोजना में बड़ा हादसा

कोरबा। कोरबा में एसईसीएल की कुसमुंडा कोल परियोजना में एक बड़ा हादसा हो गया। जहां एक कर्मचारी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला और देखते ही देखते लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। इसकी सूचना संबंधित कंपनी के अधिकारियों को दी गई वहीं कुसमुंडा पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। बताया जा रहा है कि कुसमुंडा खदान के नीलकंठ फेस में भारी वाहन की चपेट में आने से एक ठेका कर्मी की मौत हो गई। मृतक सर्वेश कुमार 42 वर्षीय सुल्तान गंज बिहार रहने वाला था जो पिछले कुछ सालों से नीलकंठ कंपनी में काम करता था। हादसे के बाद मौके पर तनाव की स्थिति निर्मित है सहकर्मी हादसे के बाद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की दोपहर लगभग 1:00 बजे खदान में काम के दौरान यह हादसा हुआ है जहां ग्रेडर मशीन की चपेट में आने से 42 वर्षीय सर्वेश कुमार चपेट में आ गया जहां उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई।

नकली पनीर फैक्टरी का खुलासा, एसडीएम ने किया सील

जांच के लिए सैपल भेजा



दुर्ग भिलाई। दुर्ग में नकली पनीर बनाने की एक फैक्टरी का खुलासा हुआ है। इस फैक्टरी में पॉम ऑयल और दूध पाइउडर के साथ एसेंस का इस्तेमाल कर न सिर्फ पनीर बनाया जा रहा था। बल्कि प्रदेश के कई शहरों में इसे बड़ी मात्रा में खपाया जा रहा था। इस फैक्टरी को लेकर दुर्ग कलेक्टर के साथ ही सांसद विजय बघेल को भी फोन कर पूरी जानकारी दी। जिसके बाद स्क्रू तहसीलदार के साथ ही कुम्हारी थाना की टीम भी मौके पर पहुंचकर अब फैक्टरी को सील कर दिया है। और अब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम पनीर का सैपल लेकर जांच के लिए लैब भेजने की तैयारी कर रही है।

नकली पनीर के बारे में तो आपने भी बहुत सुना होगा। लेकिन इसे कैसे बनाया जाता है। इस खुलासा हुआ है दुर्ग जिले के कुम्हारी अहिंवारा मार्ग में यह फैक्टरी लंबे समय से संचालित थी। एक जिसकी भनक प्रशासन के अधिकारियों को भी नहीं थी। इस फैक्टरी के अंदर तो दूध का दूध नहीं

था और पनीर का पनीर बड़ी मात्रा में था। उसे भी पॉम ऑयल और दूध पावडर से बनाया जा रहा था।

इस फैक्टरी में पनीर बनाने के लिए एक प्लास्टिक के ड्रम में बड़े मथनी से मिलावट की गई सामग्री को मथा जा रहा था। इसके बाद बड़े बड़े कंटेनर में उसे रखकर हीट किया जा

रहा था। टीन के शेड में संचालित इस फैक्टरी में स्किड मिलक पाउडर, तेल और पॉम ऑयल से बड़ी मात्रा नकली पनीर बनाया जा रहा था। इस नकली पनीर फैक्टरी के संबंध में जिला प्रशासन को दी गई। जिसके बाद एसडीएम महेश राजपूत अपने टीम के साथ कुम्हारी थाना के स्टॉफ ने फैक्टरी पहुंचकर नकली पनीर फैक्टरी का निरीक्षण किया गाय फैक्टरी को सील कर दिया गया है। पनीर फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि स्किड मिलक पाउडर, पॉम ऑयल, तेल और केमिकल मिलकर पनीर तैयार किया जाता है इस फैक्टरी में प्रतिदिन 100 से 150 किलो पनीर तैयार किया जाता है जिससे रायपुर, दुर्ग समेत अन्य जिलों में सप्लाई की जाता है।

रिश्वतखोर निकले साहब, 10 हजार रुपये लेते पकड़ा

लोगों ने पटाखे जलाकर मनाया जश्न, विवादों से रहा है पुराना नाता

बेमेतरा। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) रायपुर की टीम ने बेमेतरा जिले के साजा एसडीएम व डिप्टी कलेक्टर को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। रिश्वतखोर एसडीएम के साथ एक होम गार्ड का सिपाही भी गिरफ्तार हुआ है, जो पीडित और एसडीएम के बीच का मीडियेटर था। बीती देर रात तक एसीबी की टीम दस्तावेज कार्रवाई को पूरी कर ली। शुक्रवार को दोनों आरोपियों को बेमेतरा जिला कोर्ट में पेश किया गया। वहीं आरोपी एसडीएम टेकराम माहेश्वरी को जब एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया तो यहां लोगों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया।



लोगों का कहना है कि एसडीएम द्वारा काम के एवज में रुपये लेने की आम बात हो गई थी। ये काफी विवादों में भी रहे हैं। बीते माह अक्टूबर में साजा शासकीय कॉलेज के स्टूडेंट व्यवस्थाओं की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। इस दौरान एसडीएम टेकराम माहेश्वरी उनको समझाने के लिए पहुंचे थे, कॉलेज स्टूडेंट्स से बातचीत के दौरान वे

आगबबूला हो गए और धरने पर बैठे छात्राओं के सामने ही अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे थे। तब उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके अलावा इसी माह काम में लापरवाही के चलते कलेक्टर ने इन्हें शो कांज नोटिस भी थमाया था। बताया जा रहा है कि आरोपी एसडीएम टेकराम माहेश्वरी राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ये प्रमोट होकर डिप्टी कलेक्टर बने हैं। तीन माह पहले की बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा ने इन्हें साजा एसडीएम की जिम्मेदारी दी है।

राजनीतिक पूंजी बचाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे पवार

नीरज कुमार दुबे

राकांपा (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार के लिए इस बार का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पहले के चुनावों की तरह सामान्य नहीं है। यह चुनाव शरद पवार के लिए सिर्फ सरकार बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए भी नहीं है। शरद पवार के लिए इस बार का चुनाव अपनी जीवन भर की राजनीतिक कमाई को बचाने और धोखा देने वालों को सबक सिखाने का चुनाव भी है। हम आपको याद दिला दें कि भतीजे अजित पवार ने चाचा शरद पवार द्वारा बनाई गयी पार्टी एनसीपी पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल और धनंजय मुंडे जैसे कई नेता हैं जिनको संकट के समय शरद पवार ने राजनीतिक सहारा देकर उभारा था लेकिन वह धोखा देकर अजित पवार के साथ चले गये। इसलिए इस चुनाव में शरद पवार हर वो चाल चल रहे हैं जिससे उनको धोखा देने वालों को सबक सिखाया जा सके। जहां भावनात्मक कार्ड खेलना है वहां शरद पवार इमोशनल हो जा रहे हैं, जहां राजनीतिक चाल चलनी है वहां वह आक्रामक हो जा रहे हैं। उनको इस बार कितनी बड़ी राजनीतिक कामयाबी मिल पाती है यह तो परिणाम ही बताएंगे लेकिन इतना तो दिख ही रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति के वटवृक्ष माने जाने वाले शरद पवार दिन-रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बारामती में लोकसभा चुनावों के दौरान शरद पवार का इमोशनल कार्ड लोकसभा चुनावों में भी चला था जब उनकी बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ उनके भतीजे अजित पवार ने अपनी नीची को चुनाव में उतार दिया था। अब अजित पवार के खिलाफ उनके भतीजे रोहित पवार को उतार कर जब शरद पवार प्रचार के लिए उतरे तो उन्होंने फिर से भावनात्मक कार्ड खेला और सक्रिय राजनीति से संन्यास के संकेत दिये। एक तरफ उन्होंने बारामती में इमोशनल कार्ड खेला तो दूसरी ओर राजनीतिक कार्ड खेलते हुए अजित पवार को घड़ी चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोकने और अपनी फोटो का उपयोग करने से रोकने के लिए अदालत की शरण भी ली। शरद पवार साथ ही उन सभी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में भी जा रहे हैं जिन्होंने अजित पवार के नेतृत्व में उनको धोखा दिया। उन विधायकों के क्षेत्रों में जाकर वह उनकी कारगुजारियों से जनता को अवगत करा रहे हैं और उन्हें सबक सिखाने के लिए कह रहे हैं। इस क्रम में शरद पवार ने पूर्व सहयोगी दिलीप वलसे पाटिल के खिलाफ मोर्चा खोला। 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अंबेगांव विधानसभा क्षेत्र में शरद पवार ने कहा कि दिलीप वलसे पाटिल कहते रहे कि साबेब (शरद पवार) मेरे बारे में (कुछ भी नकारात्मक) बात नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास कहने के लिए क्या बचा है? दिलीप वलसे पाटिल ने हमें धोखा दिया, और जिन्होंने हमें धोखा दिया है उन्हें दण्डित करने की आवश्यकता है। आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि देवदत्त निकम इस सीट पर भारी अंतर से जीतें।" शरद पवार ने कहा, "जिन्हें मैंने पद, शक्ति, अधिकार और प्रतिष्ठा दी है, उनसे मैं कुछ नहीं चाहता। आज कई लोग उनसे परेशान हैं। उनके कैबिनेट में शामिल होने का फैसला लोगो को पसंद नहीं आया। उनका कहना है कि हमारे साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा, शरद पवार ने अपने पूर्व विश्वासपात्र छगन भुजबल के येवला निर्वाचन क्षेत्र में रैली को संबोधित करते हुए 2019 के चुनावों में गलत उम्मीदवार देने के लिए लोगों से माफ़ी मांगी। शरद पवार ने मतदाताओं से विश्वासघाती को हराने की भावुक अपील की, जो पिछले साल जुलाई में भुजबल के अजित पवार के साथ जाने से उन्हें लगी गहरी चोट को दर्शाते हैं। शरद पवार ने खुलासा किया कि राकांपा में फूट के बाद भुजबल उनके घर पहुंचे और उनके व अजित पवार के बीच सुलह कराने की पेशकश की, लेकिन वह दोबारा कभी नहीं आए। शरद पवार ने कहा कि भुजबल की कमियों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें नेता प्रतिपक्ष से लेकर उपमुख्यमंत्री तक कई अहम पद सौंपे गए, बावजूद इसके उन्होंने राजनीतिक शालीनता की सभी सीमाएँ लांघ दीं और उन्हें धोखा दिया। शरद पवार ने कहा कि भुजबल का उन्हें और दिवंगत बालासाहेब ठाकरे समेत अपने राजनीतिक गुरुओं को धोखा देने का इतिहास रहा है। उन्होंने मतदाताओं से इस दलबदलू नेता को सबक सिखाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, जब उन पर (भुजबल पर) कुछ आरोप लगने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा, तो मैं उनके साथ खड़ा रहा और यहाँ तक कि उन्हें महा विकास आघाडी सरकार में एक पद भी दिया। शरद पवार ने कहा कि अपने आकाओं को धोखा देने वाले भुजबल येवला के लोगों से वोट मांगने आएंगे और यह हम कराना आपके ऊपर है कि आप ऐसे धोखा का समर्थन करेंगे या नहीं।

पुराण दिग्दर्शन तीसरा अध्याय

वेदपुराण-परम्पराध्यायः

गतार्क से आगे...

विनियोग में ऋषियों और देवताओं के नाम आते हैं। जब शिष्यों की ओर से उन ऋषियों और देवताओं के चरित्र जानने के लिए प्रश्न होने लगे तो उपदेश गुरुजन उन 2 ऋषियों और देवताओं के यथाश्रुत अथवा समाधि-लब्ध चरितों को बताकर शिष्यों का समाधान करने लगे।

द्वार के अन्त तक इसी प्रकार गुरुपरम्परा द्वारा वेदों का उपदेश होता रहा और साथ 2 ऋषि और देवताओं के चारु-चरित भी कहे सुने जाते रहे। जब वेदव्यास जी ने वेदरक्षा के लिए गुरुपरम्पराश्रुत वेदों को चार भागों में विभक्त करके ग्रन्थन किया और उन्हें पैल आदि भिन्न 2 शिष्यों को प्रदान किया तब गुरु शिष्य-सम्प्रदाय-प्रचलित ऋषियों और देवताओं के चरितों को भी अष्टादश पुराण-ग्रन्थरूप में निबद्ध करके लोमहर्षण आदि शिष्यों को पढ़ाया ।

इस प्रकार पुराणों का उपदेशकाल वही है जो कि

वेदों का। और ग्रन्थरूप में निबद्ध होने का समय भी वही है जो कि वेदों का। पुराणों के वक्ता भी वही ऋषिजन हैं जो कि वेदमन्त्रों के द्रष्टा और उपदेशा थे। इन्हें पुस्तकाकार ग्रन्थन करने वाले भी वही महर्षि व्यास हैं, जिन्होंने कि वेदों का सङ्कलन किया था। यही वेद और पुराणों का समन्वय है। इस परम्परा का मानन करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। पुराणों के अध्ययन किये बिना वेदों का समझना कठिन ही नहीं किन्तु सर्वथा असम्भव है, क्योंकि मन्त्रार्थ-ज्ञान के लिये विनियोग-ज्ञान आवश्यक है, और विनियोग-वर्णित ऋषियों और देवताओं का चरित जानने के लिये पुराणों का स्वाध्याय अत्यावश्यक है।

हमारे पास पुराण ग्रन्थ ही एकमात्र साधन है जिससे कि हम ऋषियों और देवताओं के विषय में सर्वतोमुख ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

क्रमशः ...



ज्ञान/मीमांसा

एकजुट मुसलमान भी है जातियों-कुरीतियों में बंटा

संजय सक्सेना

यह बात समझ से परे है कि गैर भाजपा दलों के नेताओं को हिन्दू समाज में पिछड़े और दलित जाति के लोगों की ही चिंता क्यों सताती है। उनका ध्यान उन और दलित मुसलमानों की तरफ क्यों नहीं जाता है जो उच्च श्रेणी के मुसलमानों के कारण अपने अधिकारों से वंचित हैं। मुसलमानों में इन दलित और पिछड़े लोगों की पहचान परमांदा समाज के रूप में है। दरअसल, भारतीय मुसलमान मुख्यतः तीन जाति समूहों में बंटा हुआ है इन्हें अशराफ़, अजलाफ़ और अरजाल कहा जाता है। ये जातियों के समूह हैं, जिसके अंदर अलग-अलग जातियां शामिल हैं। हिंदुओं में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग होते हैं, वैसे ही अशराफ़, अजलाफ़ और अरजाल को देखा जाता है। अशराफ़, इसमें कथित बीच की जातियां शामिल हैं। इनकी एक बड़ी संख्या है, जिनमें खास तौर पर अंसारी, मंसूरी, राइन, कुरैशी जैसी कई जातियां शामिल हैं। कुरैशी मीट का व्यापार करने वाले और अंसारी मुख्य रूप से कपड़ा बुनाई के पेशे से जुड़े होते हैं। हिंदुओं में उनकी तुलना यादव, कोइरी, कुर्मी जैसी जातियों से की जा सकती है। तीसरा वर्ग है अरजाल। इसमें हलालखोर, हवारी, रज्जाक़ जैसी जातियां शामिल हैं। हिंदुओं में मैला ढोने का काम करने वाले लोग मुस्लिम समाज में हलालखोर और कपड़ा धोने का काम करने वाले धोबी कहलाते हैं। अरजाल में वो लोग हैं, जिनका पेशा हिंदुओं में अनुसूचित जाति के लोगों का होता था। इन मुसलमान जातियों का पिछड़ापन आज भी हिंदुओं की समरूप जातियों जैसा ही है।

राज्यसभा के पूर्व सांसद और परसमांदा मुस्लिम आंदोलन के नेता अली अनवर अंसारी कहते हैं कि मुसलमानों में भी जाति प्रथा हिंदुओं की तरह ही काम करती है। विवाह और पेशे के अलावा मुसलमानों में अलग-अलग जातियों के रीति रिवाज भी अलग-अलग हैं। मुसलमानों में भी लोग अपनी ही जाति देखकर शादी करना पसंद करते हैं। मुस्लिम इलाकों में भी जाति के आधार पर कॉलोनियां बनी हुई दिखाई देती हैं। कुछ मुसलमान जातियों की कॉलोनी एक तरफ़ बनी हुई है, तो कुछ मुसलमान जातियों की दूसरी तरफ़। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में तुर्क, लोधी मुसलमान रहते हैं। उनके बीच काफी तनाव रहता है।



उनके अपने-अपने इलाके हैं। राजनीति में भी ये देखा जाता है। अली अनवर कहते हैं कि जीने से लेकर मरने तक मुसलमान जातियों में बंटा हुआ है। शादी तो छोड़िए, रोटी-बेटी का रिश्ता भी नहीं है एक दो अपवाद को छोड़कर.जाति के आधार पर कई मस्जिदें बनाई गई हैं। गांव-गांव में जातियों के हिसाब से क़ब्रिस्तान बनाए गए हैं। हलालखोर, हवारी, रज्जाक़ जैसी मुस्लिम जातियों को सैयद, शेख़, पठान जातियों के क़ब्रिस्तान में दफ़नाने की जगह नहीं दी जाती। उनके अनुसार, कई बार तो पुलिस को बुलाना पड़ता है। मुसलमानों में कम से कम 15 ऐसी जातियां हैं, जिन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। मुसलमानों में जो पिछड़ी जातियां हैं, उन्हें ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन उससे हलालखोर जैसी जातियों के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता, जबकि उनका पिछड़ापन हिंदू दलितों जैसा है।

इस संबंध में प्रो. तनवीर फ़ज़ल बताते हैं कि धर्म परिवर्तन के समय लोग अपने साथ अपनी अपनी जातियां भी लेकर आए, इस्लाम धर्म अपनाने के बाद भी उन्होंने जाति को नहीं छोड़ा। उत्तर प्रदेश के जिन राजपूतों ने मुस्लिम धर्म अपनाया, वे अभी भी अपने नाम के साथ चौहान लिखते हैं। खुद को राजपूत मानते हैं। यह भी माना जाता है कि जो तुर्क, मुग़ल और अफ़ग़ान भारत में आए। उन्होंने अपने लोगों को शासन व्यवस्था में ऊंचा स्थान दिया और यहां के लोगों को कमतर निगाहों से देखा। प्रोफ़ेसर फ़ज़ल के अनुसार हो सकता है कि वहां से भी इसकी शुरुआत हुई हो।

खैर, यह सब बातें इस लिये बताई जा रही थीं क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विषय पर हमला बोलते हुए कहा था कि यह लोग मुसलमानों में दलित और पिछड़ों की बात क्यों नहीं करते हैं। मोदी ने कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना करवाने की मांग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा केवल हिंदू समाज की जातीय जनगणना की बात करने का उद्देश्य हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ़ भड़काना भर है, जबकि मुसलमानों की विभिन्न जातियों की

बात पर कांग्रेस मुंह बंद कर लेती है। वैसे तो मोदी के निशाने पर कांग्रेस और गांधी परिवार था, लेकिन कमोबेश यही स्थिति उन तमाम दलों की भी है जो तुष्टिकरण या मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करते हैं। इसमें समाजवादी पार्टी, बसपा, लालू यादव की पार्टी, ममता बनर्जी, केजरीवाल सभी दलों के नेता शामिल हैं।

यहां यह याद दिला देना भी ज़रूरी है

कि भले ही मोदी राज में कांग्रेस जातीय जनगणना की बात कर रही हो कांग्रेस का पूर्व नेतृत्व जिसमें नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक की सरकारें शामिल थीं ने हमेशा जातिवाद का विरोध किया था। इतना ही नहीं कांग्रेस कग नेतृत्व वाली संग्रग सरकार जिसके मुखिया मनमोहन सिंह और सुपर पीएम सोनिया गांधी थी ने वादा करने के बावजूद 2011 में हुई जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से संबंधित जातिगत गणना के आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया था। यह विडंबना ही है कि आज वही कांग्रेस और गांधी परिवार जातीय जनगणना के लिए सबसे अधिक व्याकुल है। कांग्रेस का विभिन्न मुस्लिम जातियों के बारे में चर्चा न करना और उनके बीच सामाजिक न्याय की उपेक्षा कर पसमांदा और अशराफ़ मुस्लिमों के विभेद को नकारना उसकी सामाजिक न्याय की नीति पर प्रश्नचिह्न लगाता है। प्रधानमंत्री मोदी तो लगातार मुस्लिमों की जातियों और उनके सामाजिक न्याय के संघर्ष की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करते रहे हैं, लेकिन तथाकथित सेक्युलर-लिबरल, कांग्रेसी और कम्युनिस्ट मुस्लिमों की जातियों पर चर्चा करना उचित नहीं समझते और न ही मुस्लिम समाज के सामाजिक न्याय का संघर्ष उनके लिए कोई मायने रखता है। उनके इस रवैये से पसमांदा समाज में क्षोभ की स्थिति व्याप्त होना स्वाभाविक है, लेकिन यह और बात है कि इस समाज के पास कोई सियासी विकल्प ही नहीं मौजूद है और बीजेपी पर यह समाज चाह कर भी भरोसा नहीं कर पाता है।क्योंकि बीजेपी के खिलाफ इनको दिलों में काफ़ी जहर धोला दिया गया है।

मुसलमानों में व्याप्त जातिवाद और इससे एक बड़े तबके को उसका हक नहीं मिल पाने की स्थिति में ओबीसी से संबंधित जातिगत आंकड़े प्रकट करना नितांत आवश्यक हो जाता है, ताकि शिक्षा, रोजगार एवं राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में इससे संबंधित सभी पात्र समुदायों को आरक्षण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। 1955 में आई काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट ने

अंतरराष्ट्रीय सहनशीलता दिवस

समाज, राष्ट्र एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई-झगड़ा आम हो गया है। इतना ही नहीं लोग रिश्ते-नाते भूलकर भी जान लेने और देने पर उतारू हो रहे हैं। खासकर युवा पीढ़ी में जल्द उजेजित हो जाने की समस्या तेजी से बढ़ रही है। ‘गर्म खून’ और ‘लड़कपन’ कह कर युवाओं में बढ़ रही इस दुष्प्रवृत्ति को हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जल्द उजेजित होने वाले ये लोग खुद के साथ-साथ दूसरे को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।

सहनशीलता का शाब्दिक अर्थ है शरीर और मन को अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहन करना। मानव व्यक्तित्व के विकास और उन्नयन का मुख्य आधार तत्व सहिष्णुता है। स्वयं के विरूद्ध किसी भी आलोचना को स्वीकार नहीं करना मोटे रूप में असहिष्णुता है। बताया जाता है कि



सहिष्णुता मनुष्य को दयालु और सहनशील बनाती है वहीं असहिष्णुता मनुष्य को दम्भी या अहंकारी बनाती है। अहंकार अंधकार का मार्ग है जो मनुष्य और समाज का सर्वनाश कर देती है। शेख फरीद पुकार- पुकार कर खुद को समझाते हैं, ‘ओ फरीद, अगर तेरे वैंरी तुझ पर मुकों का प्रहार करते हैं, तब भी बदले में तुम उन पर हाथ मत उठाना। तुम तो उनसे प्रीति ही करना। उन्हें आशीष देना। उनका भला मांगना और उनके पांव चूम कर चुपचाप अपने घर चले जाना।’ ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों से कहा, ‘हिंसा का प्रतिकार कभी हिंसा से नहीं करना, बल्कि सहिष्णुता से करना और अगर कोई तुम्हारे एक अंग पर प्रहार करे तो दूसरा अंग भी उसके आगे कर देना।’ आततायियों द्वारा सलीब पर चढ़ाए जाते

हुए भी ईसा मसीह ने कहा, ‘हे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं।’ सहनशीलता का जिंदगी में बहुत महत्व है। जिसने जीवन में सहन करना सीख लिया वह जिंदगी की हर जग जीत सकता है। सहिष्णुता जीवन शक्ति का पर्याय है। विश्व के देशों में सहनशीलता का निरंतर क्षरण हो रहा है। शासक एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे बयान जारी कर रहे हैं जिससे विश्व में कटुता और असहिष्णुता का बाजार गर्म हो रहा है। बात विश्व की ही नहीं, राष्ट्र एवं समाज की भी है, हर ओर छोटी-छोटी बातों पर उतेतना, आक्रोश, हिंसा के परिदृश्य व्याप्त है। विश्व सहनशीलता दिवस मनाने के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि मानव समुदाय एक दूसरे का सम्मान करें और उन भावनाओं को पुष्ट करें जिससे किसी भी स्थिति में सहिष्णुता को हानि नहीं पहुंचे।

दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेंगे ट्रंप

अजीत रानडे

डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी बार राष्ट्रपति चुना जाना दुनिया के लिए एक मोड़ घुमा देने वाली घटना है। अमेरिका का चुनावी नतीजा निर्णायक साबित हुआ, हालांकि इसके कारण पर बहस हो सकती है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या कमला हैरिस को सत्ता-विरोधी लहर का नतीजा भुगतना पड़ा या फिर ट्रंप और उनके वादे लुभावने थे? या किसी तीसरे पक्ष ने सोशल मीडिया और धनबल के जरिये चुनावी नतीजा हैक कर लिया? हालांकि यह असंभव था, क्योंकि कमला हैरिस ने अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में चुनाव अभियान चला है, ऐसे में ज्यादा संभावना यही है कि अमेरिका जलवायु वित्त में हिस्सेदारी करने के अपने वादे से मुक्त जाए। वर्ष 2015 में हुए कॉप 21 में अमेरिका ने ऐतिहासिक जलवायु समझौते पर दस्ताख्त कर विकासशील देशों के प्रति मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता जतायी थी। लेकिन 2016 में राष्ट्रपति चुने गये ट्रंप ने पहला फैसला ही पेरिस समझौते से बाहर होने का लिया था। वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में हुए कॉप 15 में विकसित देशों ने विकासशील देशों की मदद के लिए सालाना 100 बिलियन डॉलर जलवायु वित्त के तौर पर उपलब्ध कराने का वादा किया था। बीते 15 वर्ष में सिर्फ एक बार इस वादे का पूरी तरह पालन हुआ है। अमेरिका



ने 2017 से 2020 के बीच अपना वादा नहीं निभाया। ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति काल में जलवायु वित्त के मामले में अमेरिका की इस प्रतिबद्धता में और कमी आना तय है, जिससे विकासित देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन की भरपाई के तौर पर वित्तीय मदद देने और नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने का वादा कमजोर होगा। चूँकि विकसित देश ग्रीनहाउस गैस के सबसे बड़े उत्सर्जक हैं, लिहाजा उसकी भरपाई करने और जलवायु वित्त मुहैया कराने से संबंधित वार्ता ‘जलवायु न्याय’ का हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जलवायु न्याय से इनकार करेंगे। भारत को इसका नुकसान होगा, क्योंकि 2070 तक नेट जीरो तक पहुंचने के लिए 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की जरूरत पड़ेगी। यह धराशि अमेरिका समेत बहुपक्षीय स्रोतों से आने वाली है।

दूसरा बड़ा मुद्दा प्रवासन है। यह याद करना चाहिए कि बराक ओबामा ने राष्ट्रपति चुनाव के अपने अभियान में कहा था, ‘मेरी नौकरी बेंगलुरु चली गयी है’। उन्होंने यह भी कहा था, ‘बेंगलुरु को ना और बफलो को हां।’ इस धारणा ने ट्रंप समर्थकों को क्षुब्ध कर दिया कि नौकरियां आउटसोर्स हो रही हैं। हालांकि यह भ्रांत धारणा है, क्योंकि हर आउटसोर्स

नौकरी अमेरिका को ज्यादा कुशल बनाती है और उसे ज्यादा ज्यादा लाभ देती है। यही नहीं, आउटसोर्सिंग नये रोजगार सृजन के भी द्वार खोलती है। लेकिन अपनी नौकरी गंवाने वाला हर अमेरिकी बेंगलुरु पर उंगली उठाता है। ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति काल में अवैध प्रवासियों का बड़े स्तर पर निर्वासन तय है। इसके अलावा एच-1बी वीजा प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, जिससे कि भारतीयों के लिए अमेरिका में सॉफ्टवेयर से जुड़ी नौकरियां हासिल करना कठिन हो जाए। हालांकि टेक कंपनियों विदेशी प्रतिभाओं को बुलाने पर प्रतिबंध लगाने की कोशिशों का विरोध करेंगे, पर राष्ट्रपति ट्रंप के पास वैसे विरोधों को बेअसर करने के लिए पर्याप्त राजनीतिक ताकत होगी।

तीसरा मुद्दा व्यापार शुल्कों का है। ट्रंप ने रॉबर्ट लाइटहाइजर को अपना व्यापार प्रमुख बनाया है। लाइटहाइजर को छवि सख्त और संरक्षणवादी की है। हमें यह देखने को मिल सकता है कि अमेरिका सिर्फ चीन और रूस के आयातों पर ही नहीं, बल्कि भारत, यूरोपीय संघ, कोरिया और जापान के आयातों पर भी भारी-भरकम शुल्क लगाये। कनाडा, मैक्सिको और मुक्त व्यापार समझौता भागीदारों को ही संभवतः अमेरिकी उपभोक्ताओं के बीच शुल्क मुक्त प्रवेश मिले। इसका नतीजा दूसरे देशों द्वारा ‘जैसे को तैसा’ रवैया अपनाने और देशों के बीच शुल्क युद्ध शुरू होने के रूप में मिल सकता है, जैसा कि हम ट्रंप के पहले राष्ट्रपति काल में देख चुके हैं। अमेरिकी प्रशासन में चीन-विरोधी भावना प्रबल है, जिसे ट्रंप के पहले कार्यकाल, और फिर बाइडेन के राष्ट्रपति काल में देखा जा चुका है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भी इसके जारी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों

में यह शीतयुद्ध और तेज हो, तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि तकनीकी विश्व आज अमेरिका और चीन के दो शिविरों में बंट चुका है।

चौथा मुद्दा पश्चिम एशिया और यूक्रेन में चल रहे युद्धों को अमेरिकी समर्थन का है। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेन्स्की को एक बार ‘सुपर सेल्समैन’ कहा था। उनका कहना था कि जेलेन्स्की जब भी अमेरिका आते हैं, 100 बिलियन डॉलर की सैन्य व दूसरी मदद लेकर ही लौटते हैं। हालांकि ट्रंप ने ऐसा चुनाव अभियान के दौरान कहा था, लेकिन यह मानने का कारण है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यूक्रेन को दिये जा रहे समर्थन में कमी आयेगी। बेशक यूक्रेन और इस्राइल को दी गई सैन्य मदद से अमेरिकी रक्षा कंपनियों की किस्मत चमकी है। लेकिन ट्रंप निश्चित रूप से इस नीति पर पुनर्विचार करेंगे। दरअसल ट्रंप के दौर में अमेरिका वैश्विक पुलिस बनने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकता है, क्योंकि वहां यह जन भावना कर गयी है कि दुनियाभर में सैन्य और आर्थिक मदद देने का अमेरिका को कोई लाभ नहीं मिलता। अमेरिका पर 35 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, और ऊंची ब्याज दर के कारण यह बूझ निर्भर बढ़ता ही जा रहा है। वैश्विक मदद से हाथ खींच लेने पर अमेरिका के अलग-थलग पड़ जाने की आशंका है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री कोडोलीना राइस ने हाल ही में इस पर एक शानदार लेख लिखा है। ट्रंप को उन्होंने अमेरिका के इस संभावित अलगाव पर चेताया है। यह देखना होगा कि ट्रंप इस चेतावनी को गंभीरता से लेते हैं या नहीं। ट्रंप के राष्ट्रपति काल में अमेरिका को ऊंची ब्याज दर समेत भारी कर्ज और ऊंची मुद्रास्फ़ीति के लिए तैयार रहना चाहिए। अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी अपेक्षाकृत कमजोर ही बनी रहेगी।

आज का इतिहास

- 1944 ऑपरेशन क्वीन, ड्यूरेन, जर्मनी में शुरू हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे भारी मित्रवत सामरिक बम हमलों में से एक था।
- 1945 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के गठन का फैसला हुआ।
- 1945 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की स्थापना की गई थी।
- 1946 अमरीकी वैज्ञानिकों ने वातावरण में कार्बोनिक गैस के तत्व छोड़कर संसार में पहली बार कृत्रिम वर्षा करने में सफलता प्राप्त की।
- 1947 टोक्यो के सईतामा में चक्रवाती तूफान कैथलीन से 1,930 लोगों की मौत हो गई।
- 1959 रॉनार्स और हैमरस्टीन का संगीत, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, द स्टोरी ऑफ़ द ट्रैप फैमिली सिंगर्स, लॉट-फॉन्टान थिएटर में व्यापक तरीके से खोला गया।
- 1965 सोवियत संघ ने कबाकिस्तान के बैकोनूर से वेनेरा 3 अंतरिक्ष जांच को सफलतापूर्वक शुरू किया, जिसने शुक्र ग्रह की सतह पर एक लैंडिंग की जिससे यह ऐसा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना।
- 1973 अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने ट्रांस-अलास्का पाइपलाइनअथोराइजेशन एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जो आर्कटिक महासागर से अलास्का की खाड़ी तक अलास्का पिपिनेलिनेटो परिवहन तेल के निर्माण को अधिकृत करता है।
- 1975 यूनाइटेड किंगडम और आइसलैंड के बीच तीसरी कॉड युद्ध शुरू हुआ।
- 1979 बुखारेस्ट मेट्रो की पहली पंक्ति, एम 1 लाईन, रोमानिया के बुखारेस्ट में तिमपुरी नोई से सेमनतोरपिया तक खुली।
- 1988 बेनजिर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। पाकिस्तान में करीब एक दशक बाद चुनाव का आयोजन किया गया था।
- 1989 छह कैथोलिक धर्मगुरुओं सहित सैन सल्वाडोर में यूनिवर्सिटेड हेंडोरामेरिका जोस सिमेकोन्सके के आठ कर्मचारियों की संस्था सल्वाडोर आर्मी के डेथ स्क्वाड ने की थी।
- 1996 मद्र टेरेसा को मानद अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हुई।

पॉवर कंपनी की स्थापना की रजत जयंती

विकास शर्मा

बिजली है तो यह आधुनिक जीवन है। जल और वायु के बाद विद्युत मानों जीवन की अनिवार्यता हो गई है। लेकिन क्या आज की पीढ़ी इस बात को स्वीकार करेगी कि भारत में सिर्फ 150 वर्ष पहले यह विद्युत ऊर्जा शब्दकोष का हिस्सा भी नहीं था और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यह सिर्फ एक शताब्दी का मामला है। स्वतंत्रता के पश्चात देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए विद्युत ऊर्जा के महत्व को समझा गया और इसे गति प्रदान करने के लिए भारतीय विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 लागू किया गया। उस दौर में छत्तीसगढ़, सेन्ट्रल प्राविस तथा बरार प्रांत का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ समेत पूरे प्रांत की राजधानी नागपुर थी जहाँ पहली बार 1905 में बिजली के बल्ब की रोशनी को लोगों ने देखा। लेकिन छत्तीसगढ़ को बिजली के लिए लगभग एक दशक का और इंतजार करना पड़ा।

पहली बार आई बिजली

छत्तीसगढ़ में पहली बार बिजली रायपुर और बिलासपुर में नहीं बल्कि अंबिकापुर में आई। यहाँ आज से एक शताब्दी पहले 1915 में लोगों ने बिजली से नगर को रोशन होते देखा। सारंगढ़ में 1924, छुईखदान में 1926, रायपुर और राजनांदगांव में 1928, जगदलपुर और बैकुंठपुर में 1929, खैरागढ़ में 1930, रायगढ़ में 1931, बिलासपुर में अक्टूबर 1934 और जशपुर में 1941 में बिजली आपूर्ति के प्रमाण हैं। इन्हीं दशकों में

बीजापुर, कांकर समेत कई अन्य स्थानों पर छोटे पॉवर जनरेटरों के जरिए आवश्यक सेवाएं बहाल होती रही।

वालीस के दशक में भूमिगत बिजली केबल

रायपुर में कोलकाता की निजी कंपनी को विद्युत उत्पादन और वितरण का लाइसेंस दिया गया बाद में म्यूनिसिपल इलेक्ट्रीकल अंडरटेकिंग रायपुर ने इसे अपने हाथ में ले लिया। रायपुर के भाटागाँव तथा नयापारा में मौजूद पॉवर हाउस, बिजली का उत्पादन करते थे। इसमें सिर्फ 240 किलोवाट बिजली बनती थी जिससे आवश्यक सेवाओं की बहाली की जाती थी। मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल ने 15 अगस्त 1951 को रायपुर के गुडियारी में चार हजार किलोवाट के पहले पॉयलट पॉवर स्टेशन (शासकीय पॉवर हाउस) का लोकार्पण किया था। 1958 में इसकी क्षमता बढ़कर आठ हजार किलोवाट हो गई थी पर 1965 में इस बिजली घर को बंद कर दिया गया। 1940 के दशक में भी बिजली के अंडरग्राउंड केबल बिछाए गए थे। भाटागाँव से नयापारा तक 6.6 किलोवोल्ट की साढ़े चार मील की लाइन में से 2.56 मील भूमिगत थी। संयुक्त रायपुर जिले का मानिकचौरी पहला गाँव है जहाँ 1956 में लोगों ने बिजली के बल्बों से घरों को रोशन किया।

प्रदेश का विद्युत तीर्थ

छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन का पहला बड़ा पड़ाव 25 जून 1957 को आया जब तत्कालीन मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू ने कोरबा में एक सौ मेगावाट क्षमता

विचार

विद्युत ऊर्जा : एक शताब्दी का चुनौतीपूर्ण सफर



के कोरबा पूर्व ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए आधारशिला रखी। सच कहें तो इस संयंत्र की स्थापना, कोरबा को विद्युत तीर्थ के रूप में प्रतिस्थापित करने वाला कदम था। आज कोरबा में केन्द्र, राज्य और निजी क्षेत्र की कंपनियों हजारों मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहीं हैं। वर्ष 2000 के आते तक छत्तीसगढ़ में उत्पादन तथा परिषण की क्षमता तो अच्छी थी पर मध्यप्रदेश के दौर में वितरण की व्यवस्था में कभी प्राथमिकता नहीं मिली। आज की पीढ़ी उस उपेक्षा से अनभिज्ञ है। नई पीढ़ी उस अंधकार की पीढ़ी से अनजान

भी है। 1992 तक मध्यप्रदेश के 45 में से 17 जिले पूर्ण विद्युतीकृत हो चुके थे इसमें से छत्तीसगढ़ से एक भी जिला शामिल नहीं था। सिर्फ डाढ़ा इलाका बोंते हैं और यादें बहुत धुंधली नहीं हैं जब शेष मध्यप्रदेश में रबी फसल को पानी देने के लिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ की बिजली घंटों गुल रहा करती थी।

राज्य गठन से बदली तवरी

वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद गठित सरकारों ने अपनी झुंझ अपनी दलीय प्रतिबद्धताओं से परे ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाए रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी ने साहसिक निर्णय लेते हुए 15 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन (15 नवंबर 2000) कर दिया और उन्होंने राज्य के हितों से समझौता नहीं करने का स्पष्ट संदेश दिया। दिसंबर 2003 के बाद डॉ रमन सिंह का नेतृत्व, ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश के लिए मानो स्वर्णिम युग कहा जाएगा। पॉवर सरप्लस स्टेट का दर्जा हासिल करने से लेकर अधोसंरचना का

अभूतपूर्व कार्य अपने कार्यकाल में पूर्ण कराया। शासकीय से लेकर निजी भागीदारी से प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता को 20 हजार मेगावाट तक ले जाने में सफलता पाई। डॉ रमन सिंह के बाद श्री भूपेश बघेल ने ऊर्जा क्षेत्र में चल रही सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया।

संवारेगें साय, बनावेंगे शक्ति समर्थ

अब प्रदेश और ऊर्जा विभाग की बागडोर एक स्वयंदेशील राजनेता विष्णुदेव साय के हाथों में है। विकसित होते छत्तीसगढ़ की जरूरतों को मुख्यमंत्री श्री साय ने भलिभांति समझा है और दूरगामी निर्णयों की शुरुआत कार्यकाल के प्रारंभिक समय में ही कर दी है। आज प्रदेश का हर घर रोशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप अब प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा का भी हब बनाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने निर्धारित कर दिया है। राज्य की पॉवर कंपनी ने भी इस दिशा में अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए हैं। विद्युत ऊर्जा का यह सफर जो छत्तीसगढ़ में एक शताब्दी से कुछ अधिक समय पूर्व शुरू हुआ था वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ अब पूरे देश के लिए ऊर्जा प्रदेश और पॉवर हब बन चुका है। यह हमें गर्व की अनुभूति के साथ जिम्मेदारी का एहसास कराता है। आइए, हम अतीत के 'अंधकार' से किए गए संघर्षों, त्याग और दूरदर्शी निर्णयों से मिली सफलताओं की 'किरणों' को पहचाने और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जिसमें आने वाली पीढ़ी हमें किसी 'ज्योति पुंज' की तरह स्मरण कर सके।

एनएचआरसी के नए अध्यक्ष होंगे डीवाई चंद्रचूड़?

हरीश गुप्ता

राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी खबरें ज़ोरों पर हैं कि भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के पद से सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। मोदी सरकार के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि जून 2024 में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद से ही सरकार ने एनएचआरसी का शीर्ष पद खाली रखा हुआ था। यह पद खाली पड़े हुए लगभग छह महीने हो रहे हैं और इन अटकलों को बल मिल रहा है कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ इसके लिए आदर्श व्यक्ति होंगे। वर्तमान में, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद एनएचआरसी सदस्य विजया भारती सयानी अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रही हैं। सयानी को 5 जून, 2024 को एनएचआरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। खबरों की मानें तो भारत के नए प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस प्रतिष्ठित पद के लिए चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। यह पहले से ही संभावना के दायरे में था कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद कोई महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है। सिफारिश कानून मंत्रालय को भेज दी गई है और चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कानून के अनुसार, अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। पहले कानून में यह प्रावधान था कि एनएचआरसी का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होगा। लेकिन इससे समस्या पैदा हो गई क्योंकि इस पद के लिए बहुत अधिक लोग उपलब्ध नहीं थे। दायरा बढ़ने के साथ अधिनियम में संशोधन किया गया। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिशों पर की जाती है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि वे एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के चयन में क्या करेंगे। अब तक गांधी परिवार पदों के पीछे से व्यवस्था पर शासन करता रहा है। राहुल गांधी ने संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनने की प्रतिष्ठित जिम्मेदारी भी छोड़ दी। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी के पास कई जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन राहुल गांधी ने पीएसी की बागडोर अपने विश्वस्त सिपहसालार केशी वेणुगोपाल को सौंपना बेहतर समझा। लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में वे न केवल एनएचआरसी के अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया का हिस्सा हैं, बल्कि सीबीआई के निदेशक, मुख्य सतकंता आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त, लोकपाल और अन्य संस्थाओं के प्रमुखों और सदस्यों का चयन करने वाली समिति में भी शामिल हैं। अगले कुछ महीनों में राहुल गांधी ऐसी समितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमने-सामने होंगे, क्योंकि एनएचआरसी के बाद सीईसी राजीव कुमार भी 2025 की शुरुआत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। गांधी के पास विपक्ष के नेता के तौर पर कैबिनेट रैंक है, जो उन्हें संवैधानिक पद देता है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। प्रधानमंत्री के साथ पहली मुलाकात का नतीजा देखना होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने पहले ही अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रचूड़ की दिवाली पूजा पर प्रधानमंत्री को अपने आवास पर आमंत्रित करने के लिए आलोचना की है।



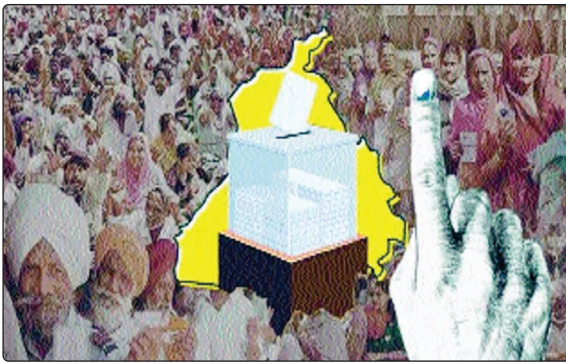
क्या कांग्रेस लोकसभा वाला अपना दबदबा बरकरार रख पाएगी

इकबाल सिंह चन्नी

लोकसभा चुनाव में पंजाब के 4 विधायकों की जीत के कारण पंजाब विधानसभा की 4 रिक्त सीटों के लिए 20 नवंबर को उपचुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 13 में से 7 सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम किया और आम आदमी पार्टी अपने दावों के उलट सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बराबर की टक्कर दी। वहाँ पंजाब की सबसे पुरानी पार्टी शिरोमणि अकाली दल-बादल इन चुनावों में एक सीट तो जीतने में कामयाब रही, लेकिन वोट प्रतिशत में काफी पीछे रह गई और भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन भाजपा ने अपना वोट प्रतिशत आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा लिया। इसे 6 से बढ़ाकर 18 फीसदी कर लिया।

मौजूदा चुनाव में अकाली दल बादल के चुनाव न लड़ने के ऐलान से बाकी पार्टियों का आंकड़ा गड़बड़ा गया है। चुनाव मैदान में उतरी तीनों प्रमुख पार्टियाँ अभी तक यह अनुमान नहीं लगा पाई हैं कि अकाली दल के पारंपरिक वोट बैंक को कौन-सी पार्टी पाएगी। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के विपक्षी नेता प्रताप सिंह बाजवा को सबसे ज्यादा चिंता अकाली दल के चुनाव न लड़ने के फैसले की है, क्योंकि अगर अकाली दल बादल और बसपा चुनाव मैदान में होते तो अकाली दल का वोट बैंक उनके प्रतिद्वंद्वी दलों में से किसी के पास नहीं जा सकता था और 4 या 5 कोणों वाले मुकाबले में कांग्रेस के लिए चुनावी माहौल काफी आसान होता।

इसी वजह से बाजवा, बादल के चुनाव न लड़ने के फैसले को अकाली दल का भाजपा के साथ आंतरिक समझौता बना रहे हैं। इन स्थितियों को देखते हुए हम उप-चुनाव वाले 4 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में संक्षिप्त विश्लेषण कर रहे हैं। अगर हम डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र पर नजर डालें तो बाजवा द्वारा व्यक्त की गई अकाली दल और भाजपा के बीच समझौते की आशंका सही नहीं लगती क्योंकि उस विधानसभा क्षेत्र का अकाली दल सुच्चा सिंह लंगह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर रहा है। और आश्चर्य की बात है कि अभी तक अकाली दल के आलाकमान की ओर से लंगह के इस फैसले के खिलाफ या पक्ष में कोई बयान नहीं आया है



जिससे जानकार अंदाजा लगा रहे हैं कि लंगह को अकाली दल के हाईकमान की सहमति मिल गई है।

इससे पिछले चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे 'आप' प्रत्याशी गुरदीप रंधावा के हौसले बुलंद हैं। मुकाबला इस बात से और दिलचस्प हो गया है कि भाजपा ने पिछली बार अकाली दल की टिकट पर कांग्रेस को टक्कर देने वाले रविचरण सिंह काहलों को अपना उम्मीदवार बना लिया है, जिसके चलते अब तक के चुनावों में 14 में से 9 बार जीत हासिल कर चुकी कांग्रेस को अपने उम्मीदवार जितेंद्र रंधावा को चुनाव जिताने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।

उप-चुनाव में गिहड़वाहा सबसे चर्चित सीट है। इस सीट पर तीनों प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों का कद बढ़ा माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने अकाली दल छोड़कर 'आप' में शामिल हुए हरदीप सिंह उर्फ डिंपी दिखें को टिकट दिया है, जो पिछली बार कांग्रेस उम्मीदवार से महज 1349 वोटों से हार गए थे, जबकि भाजपा ने 3 बार जीत चुके पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत सिंह बादल को टिकट दिया है। कांग्रेस ने यहां से 3 बार जीत चुके पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह राजा वडिंग को पत्नी अमृता वडिंग को भी उम्मीदवार बनाया है। प्रकाश सिंह बादल के करीबी मनप्रीत बादल और उनके समर्थक निकट भविष्य में भाजपा और अकाली दल बादल के बीच समझौता होने का दावा कर भाजपा के साथ-साथ अकाली दल के वोट भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीट से अमृता वडिंग, डिम्पी दिखें और मनप्रीत बादल के बीच कड़ी टक्कर होने

की संभावना है।

बरनाला क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के बागी उम्मीदवार गुरदीप सिंह बाट के मैदान में उतरने के कारण आम आदमी पार्टी के लिए सिरदर्द का कारण बना हुआ है। वहाँ बड़े नेताओं, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मीत हेयर, अमन अरोड़ा और बरिन्द्र गोयल के लिए इन्जत का सवाल बना हुआ है क्योंकि इस क्षेत्र को 'आप' की राजधानी कहा जाता है। 'आप' ने हरिंदर सिंह धालीवाल को टिकट दिया है, जो मंत्री मीत हेयर के करीबी हैं, जबकि बागी उम्मीदवार बाट को मुख्यमंत्री का करीबी माना जाता है। 'आप' के बागी उम्मीदवार की वजह से भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार इस सीट पर जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। विधायक रह चुके भाजपा प्रत्याशी केवल दिखें बरनाला के शहरी वोटों के दम पर ही जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप दिखें भी आम आदमी पार्टी में फूट का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चब्बेवाल से इस बार आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में जीते लोकसभा सदस्य राज कुमार चब्बेवाल के बेटे इशांक चब्बेवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है।

आम आदमी पार्टी सत्ताधारी पार्टी होने और उम्मीदवार के पिता के लोकसभा सदस्य होने का फायदा उठाकर यह चुनाव जीतने की उम्मीद कर रही है। कांग्रेस ने रणजीत कुमार को मैदान में उतारा है, जिन्होंने पिछली बार बसपा से लोकसभा चुनाव लड़ा था और भाजपा ने सोहन सिंह डंडल को मैदान में उतारा है, जिन्होंने पिछली बार अकाली दल बादल से विधानसभा चुनाव लड़ा था। सोहन सिंह डंडल 4 बार विधायक और एक बार मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों को 'आप' से ज्यादा मेहनत करनी होगी।

कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के प्रदेश आलाकमान ने इन चुनावों में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। दोनों बड़े नेता वडिंग और रंधावा अपनी-अपनी पत्नियों के निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर नहीं निकल सके। इसलिए आम चुनाव में कांग्रेस के लिए अपनी जीती हुई सीटों को बरकरार रखना और लोकसभा में अपना दबदबा कायम रखना एक चुनौती बनी हुई है।

मोदी और ट्रंप में हैं 5 अद्भूत समानताएं

प्रमु चावला

विश्व में अगर ऐसा कोई नेता है, जिसे जितने प्रेम करने वाले हैं, उतने ही घृणा करने वाले, तो वह ट्रंप हैं, जो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गये हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके उपयुक्त जुड़वाँ हैं, जो ट्रंप की ही तरह देशभक्ति, परंपरावाद और राष्ट्रीय पहचान में विश्वास करते हैं। वामपंथी मीडिया, हॉलीवुड की सहिष्णु शिथिलयतें और यूरोप के उदारवादी ट्रंप से घृणा करते हैं। ऐसे ही लुटियंस के बौने लोग और लगभग विलुप्त होते जा रहे धर्मनिरपेक्षता के सिपहसालार नरेंद्र मोदी के आक्रामक राष्ट्रवाद पर टूट पड़ते हैं। ट्रंप और मोदी दोनों नयी विश्व व्यवस्था में वर्चस्ववादी भूमिका में हैं। अमेरिकियों ने गैरकानूनी प्रवासन पर ट्रंप की आक्रामक मुद्रा और देश को पहली प्राथमिकता देने के पक्ष में वोट दिया। फिलीस्तीन के खिलाफ सख्त रख से ट्रंप की दबदबे वाली छवि बनी।



नाटो की फंडिंग घटाने की भी बात कही, क्योंकि उनका मानना है कि नाटो के जरिये अमेरिका की तुलना में यूरोप को अधिक लाभ मिलता है। विभाजित भारत को एकजुट करने के लिए मोदी ने भी सुरक्षित भारत की बात कही थी। **प्रवासन विरोध** : ट्रंप ने जिस सख्ती के साथ गैरकानूनी प्रवासन का विरोध किया, वही चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की जीत का आधार बना। ट्रंप ने कहा था, 'कमला हैरिस के पक्ष में एक वोट का मतलब होगा और चार-पांच करोड़ अवैध प्रवासी हमारी सीमा से प्रवेश करेंगे। वे हमारा पैसा, हमारी नौकरी और हमारा जीवन चुरा लेंगे।' वर्ष 2014 के अपने चुनाव प्रचार में मोदी ने भी अवैध प्रवासियों को मुद्दा जोर-शोर से उठाया था।

सांस्कृतिक एकरूपता : मोदी और ट्रंप, दोनों सांस्कृतिक एकरूपता के प्रबल समर्थक हैं। वर्ष 2017 में 'पॉलिटिको' मैगज़ीन ने ट्रंप को 'सांस्कृतिक युद्ध के राष्ट्रपति' के रूप में संबोधित किया था। इस चुनाव में 50 फीसदी से अधिक पॉपुलर वोट हासिल कर उन्होंने सांस्कृतिक युद्ध जीत लिया है। मोदी भी 'भारतीयता' को महत्व देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

सौमित्र पूंजीवाद : ट्रंप को कारोबार और उद्योग की विरासत बचपन में मिली। इसी तरह मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था, 'मैं एक गुजरती हूँ, जो यह जानता है कि व्यापार कैसे किया जाता है।' ट्रंप टेक्स की दर और सरकार का आकार घटाने की बात कहते रहे हैं। वैसे ही मोदी अकेले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने भारतीय कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टेक्स घटाकर 25 प्रतिशत किया। उद्यमियों को मोदी 'संपत्ति निर्माता' कहते हैं, और इनकी सरकार व्यापारियों की बेहतरी का ध्यान रखती है।

चीन विरोधी और इत्राइल समर्थक: व्यक्तिगत रूप से और वैचारिक स्तर पर चीन पर न तो ट्रंप थरोसा करते हैं,

न मोदी। पिछले राष्ट्रपति काल में ट्रंप ने अनेक चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, और इस बार भी वह चीनी आयातों पर 60 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं। भौगोलिक हकीकत भारत को चीन से आशंकित रखती है और 1962 से ही अपने क्षेत्रों को चीन से बचाने में लगा है। इसाइल भी ट्रंप और मोदी को जोड़ता है। ट्रंप ने येरुशलम को इसाइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी थी, जबकि मोदी इसाइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। दोनों नेता छत्र आंदोलन का विरोध करते हैं। ट्रंप ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों के कैम्पसों में आतंकी हिंसा का समर्थन करने वालों को देश से बाहर करने की धमकी दी, तो मोदी ने नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ हुए छत्र आंदोलन और जेएनयू में हुए आंदोलन पर सख्ती बरती थी।

सोशल मीडिया आज के नेताओं का ऑक्सिजन है। मोदी मर्यादा की उम्मीद करती भारतीय सोच को समझते हैं, इसलिए अपने फॉलोवर्स को संबोधित उनकी पोस्ट सूचनापरक और व्याख्यात्मक होती है। विपक्ष और विरोधियों को निशाना बनाने का काम वह आइट्टी सेल और अपने क्रोधोन्मत्त अनुयायियों पर छोड़ देते हैं। अमेरिका की संस्कृति अलग है, इसलिए सोशल मीडिया पर ट्रंप को पोस्ट आक्रामक और एकरफ़ा होती है। गाली-गलौज भरे ट्वीट के कारण एक्स (ट्विटर) ने ट्रंप पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन समानताओं ने मोदी और ट्रंप को एक दूसरे का दोस्त बना दिया है। मोदी इकलौते भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने चार साल में आठ बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी। टेक्सस में 'हाउडी मोदी' और अहमदाबाद में 'नमस्ते ट्रंप' जैसा आयोजन इन दोनों की दोस्ती के बारे में बताने के लिए काफी था। मोदी की टेक्सस रैली में ट्रंप को आमंत्रित किया गया था, जहां भारतीय प्रधानमंत्री ने भाजपा के नारे को बदलकर नया नारा दिया था, 'अबकी बार, ट्रंप सरकार।' ट्रंप हालांकि 2019 का चुनाव हार गये थे, उसके बाद महाभियोग, आर्थिक दंड, रीयल एस्टेट में हुए नुकसान, दोषसिद्धि और न्यायिक लड़ाई के बावजूद उन्होंने अपनी राजनीतिक मुहिम जारी रखी। 'द एंटीटिस' नाम के रियलिटी टीवी शो ने ट्रंप को घर-घर में चर्चित बना दिया। एंटीटिस का अर्थ प्रशिक्षु होता है। लेकिन प्रचलित अर्थ में न तो ट्रंप राजनीतिक प्रशिक्षु हैं, न ही मोदी। ये दोनों उस राष्ट्रवादी भौड़ के नायक हैं, जो उदारवादी विमर्श को परे कर नया इतिहास लिख रहे हैं।

करनी ही नहीं, कथनी भी बनाती है अच्छा-बुरा

विश्वनाथ सवदेव

नेता चाहे किसी भी रंग की टोपी पहनने वाले हों, सबकी कथनी एक-सी होती है। चुनाव-दर-

चुनाव देश का मतदाता अपने नेताओं द्वारा भरमाया जाता है। कुछ ऐसा ही हाल नेताओं के नारों का भी है। हर चुनाव में नए-नए नारे सुनाई देते हैं, हर चुनाव में नए-नए नारों से नेता हमें भरमाने की कोशिश करते हैं।



चुनाव-प्रचार में एक-दूसरे पर आरोप लगाना नई बात नहीं रह गई है। सब लगाते हैं इस तरह के नारे। कोई आरोप चिपक जाए तो तीर, वरना तुक्का ही सही। जिस तरह की आरोपबाजी, नारेबाजी चुनावों में होती है, वह हैरान कर देने वाली है। यह बात हमारे भारत तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में एक-दूसरे पर जिस तरह के आरोप लगाए गए वह परेशान करने वाली बात होनी चाहिए। अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र होने का दावा करता है। और हमारा भी दावा है कि सबसे पुराना गणतंत्र है हमारा देश। जनतांत्रिक व्यवस्था में हमारा विरोधी प्रतिद्वंद्वी होता है, दुश्मन नहीं। ऐसे में अनर्गल आरोपों वाली राजनीति उन सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए जो अपने आपको जिम्मेदार नागरिक समझते हैं। आरोप लगाना गलत नहीं है। पर आरोप बेवुनियाद नहीं होने चाहिए। साथ ही मर्यादाओं का ध्यान रखा जाना भी जरूरी है। बशीर बद्र का एक शेर है, 'दुश्मनी जम कर करो, लेकिन यह गुंजाइश रहे/फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा न हों।' यह बात हमारे राजनेताओं को समझ क्यों नहीं आती? मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि ऐसे लोग जब 'फिर से दोस्त' बन जाते हैं तो एक-दूसरे से आख कैसे मिलते होंगे? क्या उन्हें सचमुच शर्म नहीं आती? यह दुर्भाग्य ही की बात है कि आज हमारी राजनीति में इस तरह की शर्म के लिए कोई स्थान बचा नहीं दिख रहा। शर्म तो इस बात पर भी आनी चाहिए कि हमने राजनीति को पूरी तरह अनैतिक बना दिया है। मेरे एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र से मैंने एक बार यह जानना चाहा था कि कौनसा शब्द ठीक है, राजनीतिक या राजनैतिक? मेरे उस मित्र ने तत्काल जवाब दिया था, 'राजनीतिक ही सही हो सकता है - राजनीति में नैतिकता होती ही कहां है?' फिर हम दोनों हंस पड़े थे। पर आज सोच रहा हूँ यह बात हंसने की नहीं थी, दुखी होने की थी। पीड़ा होनी चाहिए थी हमें यह सोच कर कि हमारी राजनीति में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं बचा। करनी ही नहीं, कथनी भी हमें अच्छा या बुरा बनाती है। यह बात हमारे नेताओं को भी समझनी होगी। जब तक हम देश के 140 करोड़ नागरिकों को भारतीय के रूप में नहीं स्वीकारेंगे, बंटने और कटने की भाषा बोलते रहेंगे, हम अपने आपको विवेकशील समाज का हिस्सा नहीं मान सकते। यह मान कर भी बैठना गलत है कि राजनीति में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। जो जितने ऊंचे पद पर बैठता है, उसका दायित्व उतना ही अधिक होता है। कब समझेंगे इस बात को हमारे नेता? कब बोलने से पैतले तौलने की बात समझेंगे वे?



गुलाबी होंठों के लिए होम मेड लिप बाम: शहनाज़ हुसैन

सर्दियों शुरू होने वाली हैं। ऐसे में मौसम में बदलाव, वातावरण में नमी की कमी से होंठों का फटना आम बात होती है क्योंकि होंठों की स्किन बाकी शरीर की स्किन से ज्यादा मुलायम और कोमल होती है और इसीलिए इस पर मौसम का असर जल्दी पड़ता है।

सर्दियों में खासकर होंठों के कटने, फटने, शुष्क होने और खुरदुरे नजर आने की दिक्कत बढ़ जाती है इसलिए होंठों को मुलायम और सूखने से बचाने के लिए उनकी अच्छे से केयर करना बहुत जरूरी है। होंठों को गुलाबी और मुलायम रखने के लिए एक अच्छे लिप बाम का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है।

होंठों के केयर के लिए वैसे तो कई सारे लिप बाम पैट्रोलियम जेली मौजूद है लेकिन बाजार में मिलने वाले यह लिप बाम को बनाने में कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो होंठों को ठीक करने के बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं कई बार होंठ काले भी पड़ने लगते हैं ऐसे में अगर आप घर पर ही नेचुरल तरीके से लिप बाम तैयार करें तो कहीं बेहतर परिणाम मिलेंगे।

1. लिप बाम घर पर बनाने के लिए 8 से 10 पीस -गुलाब की पंखुड़ियां दो पीस विटामिन ई कैप्सूल, एक चम्मच कच्चा दूध और दो चम्मच एलोवेरा जेल लें। लिप बाम बनाने के लिए सबसे पहले गुलाब की पंखुड़ियों को धोकर मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें। पंखुड़ियों की पेस्ट को कांच की कटोरी में निकाल लें। अब इस पेस्ट में थोड़ा सा कच्चा दूध, विटामिन ई कैप्सूल का जेल और एलोवेरा जेल को मिला दें। इन सभी चीजों का मिश्रण अच्छे से स्मूद बना कर पेस्ट को एक कंटेनर में डालें, आपका लिपबाम तैयार हो गया है। इसे एयरटाइट कंटेनर में बंद करके फ्रीज में स्टोर करें। फ्रिज में स्टोर करने के अगले दिन आप लिप बाम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
2. घर में लिप बाम बनाने के लिए गुलाब की पंखुड़ियां, 1 चमच शहद, 1 चमच बैसलीन, और 1 चमच नारियल तेल लें। गुलाब की पंखुड़ियों को धोने के बाद एक बर्तन में डाल कर एक कप पानी में पका लें और जब जब अच्छी तरह पक जाये तो छानकर एक कटोरी में निकाल लें। अब गुलाब वाले पानी में 1 चमच शहद, 1 चमच बैसलीन, और 1 चमच नारियल



तेल मिला लें। जब यह स्मूद हो जाये तो तो इसे एक कंटेनर में डाल कर फ्रीज में रख लें। इसे आप 5 -7 घण्टे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं।

3. घर में लिप बाम बनाने के लिए 1 चम्मच शिया बटर, 1 चम्मच कोकोआ बटर, 1 चम्मच नारियल तेल, आधा चमच शहद, कुछ चुँदे विटामिन ई तेल और गुलाब जल लीजिये / अब छोटे कांच के कटोरे में शिया बटर, कोकोआ बटर और नारियल तेल को डालें। अब इन सामग्रियों को एक छोटे बर्तन में डालकर धीमी आंच पर पिघलने के लिए रखें। आप इन्हें माइक्रोवेव में भी पिघला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इनको ज्यादा गर्म न करें। जब सारी सामग्री पिघल जाए तो मिश्रण को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। फिर इसमें शहद और विटामिन ई तेल डाल कर अच्छे से मिला लें। आपका लिप बाम तैयार हो गया है / इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल कर फ्रीज में रख दें और अच्छी तरह सेट होने के बाद इस्तेमाल कर लें।
4. कुछ ही दिनों में सर्दियाँ आने वाली हैं और ऐसे में घी का लिप बाम सोने पर सुहागे का काम करेगा। इसके लिए एक बर्तन में तीन चमच घी डालकर गैस पर धीमी आंच पर रख दें और जब घी पूरी तरह से पिघल जाये तो इसमें एक चमच शहद और डेढ़ चमच नारियल तेल मिला दें / जब यह तरल फॉर्म में आ जाये तो इस मिश्रण को एक जार में डाल कर ढण्डा होने दें / ढण्डा होने के बाद इसे एक कंटेनर में डाल कर फ्रीज में रख लें और दूसरे दिन इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें

एंब्रायडिड गाउन में खुद को बॉलीवुड डीवाज की तरह करें स्टाइल



अगर आप किसी फंक्शन में एक सॉफ्ट लुक कैरी करना चाहती हैं तो ऐसे में आप सारा अली खान की तरह आइवरी कलर में हैड एंब्रायडिड गाउन को पहन सकती हैं। फुल स्लीव्स गाउन में लाइट मेकअप और ओपन हेयर लुक काफी अच्छा लगेगा।

जब किसी खास अवसर में जाने की तैयार होती है तो महिलाएं गाउन पहनने का प्राथमिकता देती है। यह एक ऐसा आउटफिट है, जो किसी भी फंक्शन में अच्छा लगता है। यूं तो आप डिफरेंट स्टाइल गाउन को पहन सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने लुक को सबसे अलग व खास बनाना चाहती हैं तो ऐसे में आप एंब्रायडिड गाउन को पहन सकती हैं। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको बॉलीवुड डीवाज के कुछ ऐसे ही एंब्रायडिड गाउन के लुक के बारे में बता रहे हैं, जो यकीनन आपको भी पसंद आएंगे-

हार्ड नेक आइवरी हैड एंब्रायडिड गाउन

अगर आप किसी फंक्शन में एक सॉफ्ट लुक कैरी करना चाहती हैं तो ऐसे में आप सारा अली खान की तरह आइवरी कलर में हैड एंब्रायडिड गाउन को पहन सकती हैं। फुल स्लीव्स गाउन में लाइट मेकअप और ओपन हेयर लुक काफी अच्छा लगेगा।

स्लीवलेस मल्टीकलर एंब्रायडिड गाउन

अगर आप एंब्रायडिड गाउन में एक ब्राइट लुक कैरी करना चाहती हैं तो ऐसे में माधुरी दीक्षित के इस एंब्रायडिड गाउन को पहना जा सकता है। ब्लू कलर के स्लीवलेस गाउन मल्टीकलर हैड एंब्रायडिड देखने में काफी अच्छे लग रही है। आप इस तरह के गाउन के साथ लाइट मेकअप कर सकती हैं। जबकि स्टेटमेंट इयररिंग्स आपके लुक को और भी अधिक खास बनाएगा।

प्लॉजिंग नेकलाइन एंब्रायडिड गाउन

अगर आप कॉकटेल पार्टी या नाइट पार्टी के लिए जा रही हैं तो ऐसे में आप रेड कलर प्लॉजिंग नेकलाइन एंब्रायडिड गाउन को पहन सकती हैं। हिना खान ने भी इस लुक में रेड कलर के प्लॉजिंग गाउन को कैरी किया है। जिसमें सीक्सेस वर्क उसे पार्टी लुक दे रहा है। आप इस गाउन के साथ चोकर पहन सकती हैं। वहीं, मेकअप के साथ आप बहुत अधिक एक्सपेरिमेंटल हो सकती हैं। मसलन, रेड गाउन के साथ रेड लिपस्टिक कैरी कर सकती हैं या फिर नाइट पार्टी लुक को ध्यान में रखकर स्मोकी आइज भी क्रिएट की जा सकती है।

सौन्दर्य को ग्रहण लगाता है प्रदूषण: शहनाज़

देश के अधिकतर शहरों के आसमान में धुएँ, धूल, एसिड से भरी जहरीली हवा की परत बार बार खतरनाक स्तर को पर कर रही है तथा अनेक शहरों की हवा साँस लेने लायक नहीं रह गई है / प्रदूषण के खतरनाक स्तर पार कर जाने से अनेक शहरों में स्मॉग की घनी चादर छाई छाई हुई है जिससे देखने में भी परेशानी का सामना करना पर रहा है / वायु में प्रदूषण आगामी दिनों में बढ़ से बढ़त हो सकता है /हालाँकि वायु प्रदूषण से सेहत को होने वाले नुकसान के बारे में ज्यादातर लोग जागरूक हैं लेकिन वायु प्रदूषण से बालों, त्वचा, चेहरे की सुन्दरता पर पड़ने वाले खतरनाक प्रभाव से कम ही लोग वाकिफ़ हैं / वायु में बढ़ते प्रदूषण से न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है लेकिन उससे आपकी खूबसूरती पर भी ग्रहण लगता है

शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण से आपको फेफड़ों के रोगों के अलावा समय से पहले बुढ़ापा,पिंगुमेंटेशन ,त्वचा के छिद्रों में ब्लॉकेज आदि अनेक सौन्दर्य समस्यायें खड़ी हो जाती हैं / ज्यादातर भारतीय शहरों में बाहनों, एयर कण्डिशन ,धुल , धुएँ आदि से आसमान में बनने वाली जहरीली धुँद की चादर से माइक्रोस्कोपिक केमिकल्स की एक परत बन जाती है जिसके कण हमारे छिद्रों के मुकबले 20 गुणा ज्यादा पतले होते हैं जिसकी वजह से बह हमारी बाहों त्वचा से हमारे छिद्रों में प्रवेश कर के त्वचा की नमी को खतम कर देते हैं जिससे त्वचा में लालिमा , सूजन ,काले दाग ,त्वचा में लचीलेपन में कमी, आ जाती हैं जिससे त्वचा निर्जीव , शुष्क , कमजोर एवं बूझी बूझी सी हो जाती है / वायु में विद्यमान रसायनिक प्रदूषण त्वचा तथा खूपड़ी के सामान्य सन्तुलन को बिगाड़ देते हैं जिससे त्वचा में रूखापन, संवेदनहीनता लाल चकत्ते, मुहाँसे तथा खुजली एवं अन्य प्रकार की एलर्जी एवं बालों में रूसी आदि की समस्यायें उभर सकती है। लेकिन अगर आप शहरों में रहते हैं तो आप प्रदूषण से कभी छुटकारा नहीं पा सकते लेकिन अच्छी खबर यह है की आप प्रदूषण से सौन्दर्य को होने वाले नुकसान को काम कर सकते हैं / आयुर्वेदिक घरेलू उपचार तथा प्राचीन औषधीय पौधों को मदद से प्रदूषण के सौंदर्य पर पड़ने वाले प्रभाव को पूरी तरह रोक जा सकता है तथा आपका सौन्दर्य सामान्य रूप से निखरा रह सकता है। प्राचीन औषधीय पौधों को घर में लगाने से वायु में विषैले तत्वों को हटाकर वायु को स्वच्छ रखा जा सकता है क्योंकि यह पौधे वातावरण में विद्यमान हानिकारक गैसों को सोखकर घर में वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। वायु प्रदूषण का सबसे खतरनाक असर त्वचा पर पड़ता है क्योंकि प्रदूषण के विषैले तत्व त्वचा पर सीधा प्रहार करके त्वचा में विषैले पदार्थों का जमाव कर देते हैं। वास्तव में यह विषैले पदार्थ त्वचा में खुजली के प्रभावकारी कारक होते हैं। वायु में विद्यमान विषैले पदार्थों का सौंदर्य पर दीघकालीन तथा अल्पकालीक प्रभाव पड़ता है त्योंहारों एवं समारोहों में चलाये जाने वाले पटाखों तथा अतिशबाजी से भी वायु में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं जिससे त्वचा में खुजली बढ़ जाती है। वायु में विद्यमान रसायनिक प्रदूषण वातावरण में आक्सीजन को कम कर देते हैं जिससे त्वचा में समय से पूर्व झुर्रियां तथा बुढ़ापे के भाव झलकना शुरू हो जाते हैं। प्रदूषण की वजह से त्वचा पर जमे मैल, गन्दगी तथा रसायनिक तत्वों से छुटकारा प्रदान करने के लिए त्वचा की सफाई अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आपकी त्वचा शुष्क है तो आपको क्लींजिंग क्रीम तथा जेल का प्रयोग करना चाहिए जबकि तैलीय त्वचा में क्लींजिंग दूध या फेशवाश का उपयोग किया जा सकता है। सौंदर्य पर प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए चन्दन, यूकेलिप्टस, पुदीना, नीम, तुलसी, घृतकुमारी जैसे पदार्थों का उपयोग कीजिए। इन पदार्थों में विषैले तत्वों से लड़ने की क्षमता तथा बलवर्धक गुणों की वजह से त्वचा में विषैले पदार्थों के जमाव तथा फोड़े, फुन्सियों को साफ करने में मदद मिलती है। वायु प्रदूषण खोपड़ी पर भी जमा हो जाते हैं। एक चम्मच सिरका तथा घृतकुमारी में एक अण्डे को मिलाकर मिश्रण बना लीजिए तथा मिश्रण को हल्के-2 खोपड़ी पर लगा लीजिए। इस मिश्रण को खोपड़ी पर आधा घण्टा तक लगा रहने के बाद खोपड़ी को ताजे एवं साफ पानी से धो डालिए। आप वैकल्पिक तौर पर गर्म तेल की थेरापी भी दे सकते हैं।

स्किन से करती हैं प्यार तो इन फूड्स को कहें ना



अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से करते हैं। लेकिन कैफीन की अधिकता स्किन के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे आपकी स्किन पर फाइन लाइन्स व झुर्रियां नजर आ सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैफीन आपकी त्वचा को निर्जलित कर सकता है। क्या आपको लगातार स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाने से भी लाभ नहीं मिल रहा है? क्या आप लगातार कॉल-मुहासों व अन्य स्किन प्रॉब्लम्स से जूझ रही हैं? क्या एक अच्छा स्किन केयर रूटीन भी आपकी स्किन को ग्लोइंग नहीं बना रहा है? क्या आप बार-बार अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बदल-बदलकर थक चुकी हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो हो सकता है कि आप अपने आहार पर ध्यान ना दे रही हों। आपको शायद पता ना हो, लेकिन आपका खान-पान सिर्फ आपकी सेहत ही नहीं, बल्कि स्किन को भी प्रभावित कर सकता है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बता रहे हैं, जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं-

प्रोसेस्ड मीट

प्रोसेस्ड मीट जैसे बेकन या हॉटडॉग में नाइट्रेट और सोडियम काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह दोनों ही स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नाइट्रेट आपकी स्किन में सूजन और झुर्रियों की वजह बन सकता है, वहीं सोडियम की अधिकता स्किन को समय से पहले बुढ़ा और रूखा बना

सकती है। **गाय के दूध से बने डेयरी उत्पाद** यूं तो डेयरी प्रोडक्ट को सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन गाय के दूध से बने डेयरी प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि गाय का दूध और गाय के दूध से बने अन्य डेयरी उत्पाद इंसुलिन के स्तर को बढ़ाते हैं। जो कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ाता है और सीबम उत्पादन को रूँक करता है। जिससे आपकी स्किन में एक्ने व ब्रेकआउट्स की समस्या हो सकती है।

कैफीन

अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से करते हैं। लेकिन कैफीन की अधिकता स्किन के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे आपकी स्किन पर फाइन लाइन्स व झुर्रियां नजर आ सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैफीन आपकी त्वचा को निर्जलित कर सकता है। जिससे आपकी स्किन अधिक थिन हो सकती है और उसमें रिकवर्स नजर आ सकते हैं।

हार्ड ग्लाइसेमिक फूड

सफेद ब्रेड, सफेद पास्ता और आलू आदि की हार्ड ग्लाइसेमिक फूड की श्रेणी में रखा जाता है। यह ना केवल वजन बढ़ने की वजह हो सकते हैं, बल्कि इससे आपकी स्किन को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे फूड्स के कारण व्यक्ति को ब्रेकआउट्स, पिंपल्स सहित समय से पहले उम्र बढ़ने के संकेतों की समस्या भी हो सकती है।

खूबसूरत रंगीन लहंगे में बिखरे हुस्न का जादू

बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर उन हसीनाओं में से एक हैं, जो अपने स्टाइल स्टेटमेंट से लोगों को अट्रैक्ट करने में हमेशा ही कामयाब रहती हैं। छल ही में एक्ट्रेस अपने लहंगा लुक के कारण सुर्खियों में हैं। एक्ट्रेस हमेशा खुद को बेहद खूबसूरती से तैयार करती हैं। जान्हवी के लुक में सबसे खास बात यह है कि वह अपने फिगर के मुताबिक कपड़ों को पहनना पसंद करती हैं और इसमें उनकी पर्शनैलिटी निखारकर सामने आती है। लेटेस्ट फोटो में उन्होंने हर लाल रंग के रंगीन लहंगे को कैरी किया है।

हसीना इन दिनों फिल्म मिली का प्रमोशन कर रही हैं। जिसके लिए उन्होंने इस आउटफिट को पहना था। जिसमें एक्ट्रेस काफी गार्जियस दिख रही थी। इस खूबसूरत लहंगे पर कई रंग दिख रहे थे, जिसमें रेड, गोल्डन, ग्रे, व्हाइट जैसे काफी ब्राइट रंग हैं। इस स्टाइलिश लहंगे में जान्हवी की कर्वी फिगर अच्छे से फ्लॉन्ट होती नजर आ रही थी।

स्टैपी ब्लाउज ने लगाए चार चांद

जाह्वी के इस लहंगे को बोल्ट बनाने का काम उनके खूबसूरत से स्टैपी ब्लाउज ने किया है। वहीं स्टैपी स्लीव्स के साथ खूबसूरत नेक पैटर्न कमाल लग रहा है। ब्लाउज भी लहंगे की मैचिंग का ही है।

लुक में मेकअप को रखा स्पेशल

जाह्वी ने इस खूबसूरत लहंगे के साथ वेवी कलर के साथ अपने बालों को खुला रखा था। इसी के साथ जाह्वी ने मिनिमल मेकअप के साथ अपने लुक को पूरा किया है। एक्ट्रेस ने न्यूड आईशैडो, ब्लैक आईलाइनर, ब्लैक कोहल काजल, मस्कारा से लदी पलकें और न्यूड लिपस्टिक के साथ लुक को कम्पलीट किया है।

जल्द होने वाली है शादी तो आपके खूब काम आएगी ये लिस्ट, काम हो जाएगा आसान



शादी दो लोगों का पवित्र बंधन होती है। ये हर जोड़े के लिए खास होती है। हालांकि, शादी के इस बंधन में बंधने से पहले कपल को काफी तैयारियां करनी पड़ती हैं। ऐसे में कई बार खूब सारी तैयारी के बीच कुछ जरूरी सामान मिस हो ही जाता है। इससे बचने के लिए हम लेकर आए हैं शॉपिंग लिस्ट स्पेशली दुल्हन के लिए। ये लिस्ट आपके काम को काफी हद तक आसान बना देगी।

साड़ी- साड़ी एक ऐसी चीज है जिसे हर दुल्हन अपने सूटकेस में कैरी करती है। अगर आप उन्हें पहनना पसंद करती हैं, तो अलग-अलग तरह की साड़ियों को खरीद सकती हैं। अपने कलेक्शन में एक या दो प्री-ड्रेड साड़ी या कॉन्सेप्ट साड़ी रखना भी एक अच्छा ऑप्शन है।

मल्टी पर्पज ब्लाउज- वैसे तो साड़ी के साथ ब्लाउज आते हैं, लेकिन कुछ अच्छे रेडी मेड ब्लाउज डिजाइन रखें। अगर आप अपने लुक को बदलना चाहती हैं, तो स्टाइलिश बोट नेक से लेकर ब्रोकेड बेसिक्स तक, 5-6 एक्सट्रा ब्लाउज अपने पास रखें।

बेसिक सूट सेट- शादी के बाद बेहतरीन कपड़े पहनना चाहती हैं, तो कुछ स्मार्ट सूट्स को शामिल करें। हालांकि, 5-6 बेसिक सूट कैरी करें जो पैंट, पलाजो, चूड़ीदार और स्कर्ट के साथ आते हैं।

हल्के लहंगे और एथनिक ड्रेसेस- एथनिक कपड़े पहनने में आसान होते हैं। ये काफी आकर्षक होते हैं। ऐसे में कम से कम 2-3 एथनिक ड्रेस जरूर खरीदें। इसी तरह अपने बैग में एक या दो हल्के लहंगे रखें। ये पूजा से लेकर दूसरे फंक्शन तक में काम आएंगे।

वेस्टर्न वियर

शादी के बाद आप अपनी पुरानी अलमारी से सभी तरह के कपड़े तो लेकर नहीं जा सकते, लेकिन कुछ सिलेक्टिव कपड़े रख सकती हैं। आप कुछ इंडो-वेस्टर्न आउटफिट्स को अपने साथ रख सकती हैं। आप 2 से 3 जोड़ी जींस, 1 से 2 पैंट, लगभग 5 से 7 टी शर्ट, 5 से 6 टॉप और 3 से 4 ड्रेसेस साथ रखें।

नाइट वियर

अपने नाइटवियर के लिए, उन वस्तुओं को ले जाएं जिनमें आप आराम से सो सकते हैं।

अदाणी के घर हुई बैठक के बारे में शरद पवार ने किया खुलासा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने तीन साल पहले गौतम अदाणी के घर पर हुए डिनर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इससे पहले उनके भतीजे अजीत पवार ने इस डिनर की चर्चा की थी। पवार ने स्वीकार किया है कि वे गौतम अदाणी के घर पर डिनर के दौरान भाजपा नेता अमित शाह से मिले थे। उस दौरान उनके सहयोगी रहे प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार भी मौजूद थे।

पवार ने कहा कि उनके कुछ सहयोगी बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने दावा किया है कि उनके कुछ सहयोगियों को आश्वासन दिया गया था कि उनके खिलाफ चल रहे केंद्रीय एजेंसियों के मामले वापस ले लिए जाएंगे। पर उन्हें इसका भरोसा नहीं था। एक न्यूज पोर्टल को पवार ने बताया कि उनके सहयोगियों ने उनपर बीजेपी नेताओं से मिलकर यह ऑफर खुद सुनने का दबाव डाला था। इसके बाद ही पवार अमित शाह से मिलने गौतम अदाणी के घर डिनर पर गए थे।

फडणवीस ने किया बंटेंगे तो कटेंगे नारे का बचाव

मुंबई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बंटेंगे तो कटेंगे नारे का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष के कथित सेक्युलरिज्म पर भी तंज कसा और कहा कि विपक्ष के सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ हिंदू विरोध है। फडणवीस ने अजित पवार को लेकर कहा कि वे लंबे समय तक हिंदू विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों के साथ रहे, इसलिए उन्हें बदलने में थोड़ा समय लगेगा।

महायुति की सहयोगी पार्टी एनसीपी के नेता अजित पवार ने योगी आदित्यनाथ के बंटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध किया है और कहा है कि ऐसे नारों के लिए महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। इस पर फडणवीस से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि %अजित पवार कई दशकों तक एसी पार्टियों के साथ रहे हैं, जो खुद को कथित सेक्युलर बताती हैं। वे ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, इसलिए उन्हें लोगों की भावनाएं समझने में थोड़ा समय लगेगा।

बंटेंगे तो कटेंगे नारे का अजित पवार ने फिर किया विरोध

मुंबई। महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन महायुति में बंटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर दो गुट बनते दिख रहे हैं। एक वो जो इसके समर्थन में हैं, वहीं दूसरा इसके खिलाफ है। जो गुट बंटेंगे तो कटेंगे नारे के खिलाफ हैं उसमें राज्य के मौजूदा डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार और भाजपा नेता पंकजा मुंडे जैसे नाम हैं, जबकि इसके समर्थन में राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस सरीखे लोग शामिल हैं।

डिप्टी सीएम अजित पवार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बंटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध किया और कहा, मैंने इस मामले में पहले ही सार्वजनिक तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ भाजपा नेताओं ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी है। सबका साथ, सबका विकास का मतलब है सबके साथ, सबका विकास... अब, एक ही तो सुरक्षित है... मैं इसे इस नजरिए से देखता हूँ। अजित पवार ने आगे कहा, हम सभी ने इसका विरोध किया है।

दुश्मनों के खिलाफ एकजुट हों भारतीय : गडकरी

मुंबई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने योगी आदित्यनाथ के नारे बंटेंगे तो कटेंगे का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को इस नारे का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए और देश के दुश्मनों और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए।

गडकरी ने ये भी दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में महायुति गठबंधन की सरकार सत्ता में वापसी करेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती हैं, कुछ लोग मंदिर जाते हैं तो कुछ मस्जिद और कुछ गिरजाघर, लेकिन आखिर में तो हम सब भारतीय हैं। हमें बंटेंगे तो कटेंगे नारे का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए बल्कि आतंकवाद और देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। सभी भारतीयों को एकजुट होना चाहिए और वे किसी को बांटने के लिए नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा के दौरान ये नारा दिया था।

महाराष्ट्र की जनता को मोदी के बातों पर भरोसा नहीं : राउत

मुंबई। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के साथ ही देश भर में 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और दो राज्यों की दो लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव को लेकर इन दिनों देश की सिyasi सी सरगमी बड़ी हुई है। महाराष्ट्र में एक चरण तो झारखंड में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। दोनों राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। इस बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने केंद्र और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि, महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री के बयान पर भरोसा नहीं करती। यह महा विकास अघाड़ी है। हम तीनों साथ हैं। हम एक हैं और हम महाराष्ट्र में आपसे ज्यादा सुरक्षित हैं। और दूसरी बात यह है कि जनता तय करेगी कि किसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है... मैंने पहले भी कहा है कि 23 नवंबर के बाद महायुति नहीं रहेगी क्योंकि कोई सीएम नहीं होगा। वे एकनाथ शिंदे को सीएम या एलओपी नहीं बनाएंगे। उन्हें बहुत नहीं मिलेगा। हम सरकार बना रहे हैं।

झारखंड राज्य की स्थापना दिवस पर बोले राहुल गांधी

'इंडि' गठबंधन झारखंड के लोगों की संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध

नयी दिल्ली। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर हुई थी। यह दिन आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती का दिन है। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता कार्यकर्ता और लोक नायक थे जो मुंडा जनजाति से थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश राज के दौरान बंगाल प्रेसीडेंसी (अब झारखंड) में उठे आदिवासी धार्मिक सहस्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। विद्रोह मुख्य रूप से खूंटी, तमार, सरवाड़ा और बंदगांव के मुंडा बेल्ट में केंद्रित था।

अब खास दिन पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने झारखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुक्रवार को बधाई देते हुए कहा कि 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) गठबंधन उनकी संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। राहुल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "भरपूर प्राकृतिक, सांस्कृतिक और खनिज संपदा से युक्त झारखंड के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।" उन्होंने कहा, "झारखंड वासियों की सभ्यता और अधिकारों की रक्षा के लिए 'इंडिया' सदैव संकल्पित है।"

गांधी ने साथ ही लिखा, "आदिवासी महानायक, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। आदिवासी अस्मिता के लिए उनका संघर्ष और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए उनका बलिदान हमें सदा प्रेरित करता रहेगा।" कांग्रेस अध्यक्ष



मल्लिकार्जुन खरगे ने भी झारखंड के लोगों को शुभकामनाएं दीं और उनके सुख, समृद्ध एवं खुशहाल भविष्य की कामना की। खरगे ने आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को भी उनकी जयंती पर बधाई दी।

खरगे ने 'एक्स' पर लिखा, "जल-जंगल-जमीन एवं आदिवासी सभ्यता व संस्कृति की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 'उलगुलान' करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन। वे करोड़ों भारतीयों के प्रेरणास्रोत हैं एवं रहेंगे।" उन्होंने कहा, "प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण झारखंड राज्य के सभी बहन-भाइयों को झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। आने वाला कल आप सभी के लिए सुख, समृद्ध एवं खुशहाल बने, हमारी यही कामना है।"

झारखंड राज्य आधिकारिक तौर पर 2000 में मुंडा की जयंती पर अस्तित्व में आया। गांधी और खरगे ने लोगों को गुरु नानक जयंती की भी शुभकामनाएं दीं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती मनायी जा रही है।

प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जमुई में आदिवासियों को 6,640 करोड़ रुपये की दी सौगात

जनजातियों को पिछली सरकारों ने नहीं पूछा-मोदी

जमुई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बिहार के जमुई से 6,640 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोदी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित एक समारोह में भाग लेने के लिए जमुई आए हैं। बिरसा मुंडा एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें छोटानागपुर पठार के आदिवासी समुदाय के लोग प्रेमपूर्वक "भगवान" कहते हैं। मोदी ने राज्य की राजधानी से लगभग 200 किलोमीटर दूर जमुई जिले के एक सुदूर गांव में "जनजातीय गौरव दिवस" के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण भी किया। उन्होंने पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत आदिवासी परिवारों के लिए बनाए गए 11,000 घरों के गृह प्रवेश में भी वचुंअल माध्यम से भाग लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है और आज गुरु नानक देव जी का 555 वां प्रकाश पर्व भी है। मैं सभी देशवासियों को इन पर्वों की बधाई देता हूँ। आज का दिन हर देशवासी के लिए एक और वजह से ऐतिहासिक है। आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस है। मैं सभी देशवासियों को और खासतौर पर अपने आदिवासी भाई-बहनों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि आज जब हम जनजातीय गौरव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं तब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस आयोजन की आवश्यकता क्यों हुई? ये इतिहास के एक बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का एक इमानदार प्रयास है।



प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए, सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने के लिए कोशिश की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये कि भारत की आजादी के लिए केवल एक ही दल को श्रेय दिया जाए। लेकिन अगर एक ही दल, एक ही परिवार ने आजादी दिलाई तो भगवान बिरसा मुंडा का उल्लुलान आंदोलन क्यों हुआ था? संथाल क्रांति क्या थी? कोल क्रांति क्या थी? जिसको पिछली सरकारों ने नहीं पूछा, उसे मोदी पूजता है। पीएम मोदी ने कहा कि यह देश

आदिवासी भाइयों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता है। एनडीए का सोभाय है कि द्रोपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। सीएम नीतीश बाबू ने पूरे देश से उन्हें जीताने की अपील की थी। द्रोपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बनीं तो वह अतिपिछड़ी आदिवासियों का चिन्तन करती थीं। इनके बारे में पिछली सरकारों नहीं सोचती थी। इनके लिए पीएम जनमन योजना शुरू की गई। इससे देश के पिछड़े आदिवासियों का विकास हो रहा है। आज इस योजना का एक साल पूरा हो रहा है। पिछड़ी जनजातियों को घर, बिजली और सड़क का लाभ दिया जा रहा है। जिसको पिछली सरकारों ने नहीं पूछा, उसे मोदी पूजता है। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासियों इलाके में आयुष्मान आरोग्यम मंदिर बनाए जा रहे हैं। प्रकृति प्रेमी आदिवासी समाज की बातें पूरी दुनिया में बताने की कोशिश करता हूँ। आदिवासी समाज प्रकृति, सूर्य और वायु को पूजने वाला समाज है। देश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन बनाए जाएंगे। इसमें हजारों पेड़ लगाए

जाएंगे। इसमें सभी लोगों का सहयोग चाहिए। एक बार फिर से आपसभी को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहते हुए पीएम मोदी ने अपना संबोधन खत्म किया। वहीं, इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश के लिए एक-एक काम कर रहे हैं और बिहार की भी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। आज जमुई में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के नायक थे जिन्होंने जनजातीय समाज के लोगों के लिए संघर्ष किया था। उनके जन्म के समय बंगाल, बिहार, ओडिशा सब एक ही राज्य थे... झारखंड वर्ष 2000 में अलग राज्य बना। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड राज्य बनाने का निर्णय लिया... देश की आजादी और आदिवासी समाज के उत्थान में भगवान बिरसा मुंडा का बड़ा योगदान रहा।

मोदी के विमान में तकनीकी खराबी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान में शुक्रवार को तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण विमान को देवघर एयरपोर्ट पर ही रुकना पड़ा, जिससे उन्हें राष्ट्रीय राजधानी लौटने में कुछ देरी हुई। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिल्ली जा रहे विमान में झारखंड के देवघर एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उन्हें राष्ट्रीय राजधानी लौटने में देरी हुई। यह घटना उस समय हुई, जब पीएम मोदी चुनावली राज्य में अपने कार्यक्रम समाप्त कर दिल्ली लौटने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। सुरक्षा उपाय के तौर पर विमान को उतार दिया गया, जबकि तकनीकी टीमों समस्या की पहचान करने और उसे हल करने में जुटी रहीं।

खेल प्रमुख समाचार

टिम साउदी ने किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और तेज



गेंदबाज टिम साउदी ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज उनके करियर की आखिरी सीरीज होगी। वह न्यूजीलैंड के क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

इंग्लैंड के खिलाफ हैमिल्टन में होने वाले तीसरे और आखिरी टेस्ट उनके करियर का भी अंतिम टेस्ट होगा। जो उनका घरेलू मैदान है। हालांकि, इस तेज गेंदबाज ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर कौी टीम अगले साल जून होने वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचती है तो वह इस टेस्ट में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि, न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करना मेरा वह सपना था। जो मैं बड़े होते हुए देखता था ब्लैककैप्स के लिए 18 सालों तक खेलना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और सौभाग्य की बात है। लेकिन अब इस समय पर पहुंचकर ऐसा लगता है कि ये उस खेल से हटने का सही समय है। जिसने मुझे बहुत कुछ दिया।

उन्होंने कहा कि, मेरे दिल में दो टेस्ट क्रिकेट एक बहुत ही खास जगह रखती है। तो उस विरोधी टीम के खिलाफ ही बड़ी टेस्ट सीरीज खेलना, जिसके खिलाफ मैंने अपने करियर का आगाज किया था और उन्हीं तीनों मैदान पर खेलना, जो मेरे लिए बहुत खास रहे हैं। मुझे ये ब्लैक कैप्स के साथ अपने करियर का अंत करने के लिए परफेक्ट टाइम लगता है।

आर्थिक/वाणिज्य/वित्त/प्रमुख समाचार

एसबीआई ने ब्याज दरों में की बढ़ोतरी

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़ी सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों को झटका दिया है। एसबीआई से अब कर्ज लेना महंगा हो गया है। एसबीआई ने 15 नवंबर 2024 से कर्ज पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। बैंक ने लेटेस्ट मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (एमसीएलआर) की घोषणा करते हुए ब्याज दरों में 5 बेसिस प्वाइंट्स तक की बढ़ोतरी की है जो आज से ही लागू हो चुका है। तीन महीने की अवधि वाले एमसीएलआर को 8.50% से बढ़ाकर 8.55% कर दिया गया है। छह महीने का एमसीएलआर अब 8.85% से बढ़कर 8.90% हो गया है। एक साल का एमसीएलआर अब 9.5% से बढ़कर 9% हो गया है। दो और तीन साल के एमसीएलआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, दो साल के एमसीएलआर का रेट 9.05% और तीन साल का 9.10% है।

देश का निर्यात अक्टूबर में 17.25 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। भारत का वस्तु निर्यात अक्टूबर 2024 में 17.25% की बढ़ोतरी के साथ 39.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो दो साल का सबसे बड़ा उछाल है। पिछले वर्ष इसी महीने में यह 33.43 अरब डॉलर था। हालांकि, व्यापार घाटा 27.14 अरब डॉलर रहा। आयात भी 3.9% बढ़कर 66.34 अरब डॉलर हो गया, जिसमें कच्चे तेल का आयात 13.34% बढ़कर 18.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अक्टूबर में व्यापार घाटा पिछले वर्ष के 30.42 अरब डॉलर की तुलना में कम लेकिन इस साल सितंबर के 20.78 अरब डॉलर से अधिक रहा। चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीने (अप्रैल-अक्टूबर) में निर्यात 3.18% बढ़कर 252.28 अरब डॉलर और आयात 5.77% बढ़कर 416.93 अरब डॉलर हो गया, जबकि इस अवधि का कुल व्यापार घाटा 164.65 अरब डॉलर रहा।

टीमलीज के बाद अब सीआईईएल आईपीओ लांच करने की तैयारी में

नई दिल्ली। एचआर सांयूशन प्रोवाइडर सीआईईएल एचआर सर्विस शुक्रवार को शुक्रवार को करीब 450 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स फाइनल करेगी। यह जानकारी सूत्रों से मिली है। यह कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली दूसरी एचआर कंपनी होगी। इससे पहले टीमलीज सर्विस लिस्टेड है। टीमलीज रिक्वायरमेंट का काम करती है, जबकि सीआईईएल पूरी एचआर सर्विस देती है। सीआईईएल का इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) करीब 350 करोड़ रुपये के फ्रेज इश्यू और पुराने शेयरहोल्डर्स के ऑफर फॉर सेल के साथ आएगा। यह जानकारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इंडस्ट्री से जुड़े सोर्सिस ने दी है। इस आईपीओ के लीड मैनेजर्स Ambit, Centrum Capital और एचडीएफसी बैंक हैं। स्टॉफिंग इंडस्ट्री में लंबे अनुभव की वजह से सीआईईएल ने पिछले कुछ सालों में तेज प्रोथ की है।

भारत में परिवहन के अवसर बहुत बड़े हैं: उबर

नई दिल्ली। ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी उबर के भारत एवं दक्षिण एशिया के अध्यक्ष प्रभजोत सिंह ने कहा कि भारत मात्रा के हिसाब से सबसे बड़े बाजारों में से एक है और यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इसे एक "अत्यंत महत्वपूर्ण बाजार" करार दिया जो इस 'राइड-हाइलिंग' मंच को कई दशक तक अवसर उपलब्ध करा सकता है। हालांकि अभी तक इनका समुचित इस्तेमाल नहीं हुआ है। सिंह ने कहा कि भारत में परिवहन के कई अवसर हैं और कंपनी का मानना है कि उत्पादों तथा सेवाओं की बेहतर श्रृंखला व मजबूत वृद्धि के बावजूद कंपनी ने "अभी महज शुरुआत ही की है।" उबर इंडिया के शीर्ष अधिकारी ने कहा, "हालांकि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।"

पूँजीगत व्यय में कमी का क्या है अर्थ?

अधिक की समेकित वार्षिक वृद्धि देखने को मिलती है। यह एक असाधारण उपलब्धि है। यह वृद्धि तब निश्चित हुई जब मंत्रालयों और राज्यों को व्यय वितरण पर नजर रखी गई ताकि किसी तरह की बरबादी या दुरुपयोग न हो। व्यय की गुणवत्ता सुधारने के लिए कदम उठाए गए और यह निश्चित करने का प्रयास किया गया कि केंद्र सरकार के मंत्रालय अपना व्यय वर्ष की अंतिम तिमाही में नहीं खर्च करें या राज्य अपने व्यय को केंद्र से प्राप्त राशि के स्थान पर व्यय न करें। अब लगता है इन नियमों को शिथिल किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूँजीगत व्यय में वृद्धि को चालू वर्ष में भी बरकरार रखा जाए।

खबरों के मुताबिक वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि नकदी प्रबंधन दिशानिर्देशों के तहत लगे नियंत्रणों को 2025 की जनवरी-मार्च तिमाही में शिथिल किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में केंद्रीय मंत्रालय और विभाग इस वर्ष की अंतिम तिमाही में अपने सालाना पूँजीगत व्यय अनुमान का 33 फीसदी खर्च कर सकते हैं। यह कदम केंद्र को पूँजीगत व्यय बढ़ाने में सहायक हो सकता है लेकिन मौजूदा संदर्भ में नकदी प्रबंधन दिशानिर्देशों को शिथिल करने का कदम समझदारी भरा नहीं है। पूँजीगत व्यय को जब हड़बड़ी में साल खत्म होने के पहले लक्ष्य पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इस कवायद का उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

अर्थव्यवस्था इससे लाभान्वित नहीं हो पाती है। नकदी-प्रबंधन जैसे तात्कालिक हल अपनाने के बजाय सरकार के लिए बेहतर होगा कि वह यह देखे कि पूँजी खर्च होने की गति धीमी क्यों पड़ गई है। समस्या की प्रकृति को चिह्नित करना जरूरी है। केंद्र सरकार का पूँजीगत व्यय 2024-25 की पहली तिमाही में 35 फीसदी गिरा। इसी अवधि में आम चुनाव हुए थे और पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे सप्ताह में पेश किया जा सका। दूसरी तिमाही में पूँजीगत व्यय की गति ने जोर पकड़ा लेकिन इसमें केवल 10 फीसदी का इजाफा हुआ। स्पष्ट है कि पहली तिमाही के झटके से उबरने के लिए यह पर्याप्त नहीं था।

ऐसे में 2024-25 की पहली छमाही में पूँजीगत व्यय में कुल मिलाकर 15 फीसदी की कमी आई। अक्टूबर 2024 के बाद से केंद्र सरकार के लिए पूँजीगत व्यय को इतना बढ़ाना मुश्किल होगा ताकि वह 17 फीसदी

मुख्यमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस पर बैगा गुनिया, सिरहा को दी सम्मान निधि की सौगात

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बैगा, गुनिया, सिरहा को दी सम्मान निधि की सौगात



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने साईंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय समाज का इतिहास बहुत समृद्ध और गौरवशाली है। पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय समुदाय के मान, सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया है। अटल ने जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए पृथक से मंत्रालय बनाया और इस समुदाय के विकास को एक नई दिशा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समुदाय के तहत 24,000 करोड़ रूपए और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 80,000 करोड़ रूपए का बजट प्रवधान किया है, जिसके चलते जनजातीय इलाकों में तेजी से बुनियादी सुविधाओं का विकास और जनजातियों की बेहतरी के काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती वर्ष समारोह के

अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बैगा, गुनिया, सिरहा लोगों के लिए मुख्यमंत्री सम्मान निधि दिए जाने की घोषणा की। इसके तहत उन्हें प्रति वर्ष 5 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने जनजातीय गांवों में धार्मिक एवं मांगलिक कार्य के लिए अखरा निर्माण विकास योजना शुरू करने और जनजातीय समुदाय के शहीदों की प्रतिमाएं चिन्हित स्थलों पर स्थापित किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने समारोह में जनजातीय समुदाय के विभूतियों, राज्य में हुए जनजातीय विद्रोह के शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने जनजातीय चित्रकला प्रतिযোগिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर वन अधिकार अधिनियम से संबंधित 'एटलस', कैलेण्डर 'शौर्याजलि' तथा 'हल्बा जनजातीय की वाचिक परंपराएं' विषय पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। इनका प्रकाशन

छत्तीसगढ़ आदिम जाति विकास विभाग द्वारा किया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राज्यसभा सांसद अरूण सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में सभी वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की लोकप्रियता और विनम्रता की सराहना पूरे देश में होती है। उन्होंने कहा कि रायपुर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस एवं अंतर्राज्यीय नृत्य महोत्सव समारोह में आकर 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' का दर्शन हुआ है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के इस विशेष आयोजन के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को बधाई दी। उन्होंने इस मौके पर जनजातीय समुदाय के महापुरुषों को नमन करते हुए कहा कि वही देश और समाज का गौरव है, जो अपनी संस्कृति और अपने महापुरुषों को याद रखता है। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेतान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए चिंता की है।

भूपेश बघेल के एक्स पोस्ट पर भाजपा ने कहा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जयश्रीवास्तव ने शराब के लिए आबकारी विभाग द्वारा मनपसंद एप लॉन्च किए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई टिप्पणी को कोरा प्रलाप बताते हुए कहा कि शराब के कारबोर को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले बघेल को कम-से-कम अपना गिरेबाँ तो झाँक लेना था। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि शराब घोटाला और

अवैध शराब बेच के सरकारी खजाना लूटने वाले थोड़ी शर्म करें

हजारों करोड़ रूपए के दीगर घोटाले करने वाली कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को ऐसी ओछी टिप्पणियाँ करने पर शर्म महसूस करने चाहिए। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रीवास्तव ने कहा कि राजनीतिक निर्लज्जता की सीमाएँ लांघते बघेल को यह याद रखना चाहिए कि कांग्रेस के शासनकाल में शराब के दो कांटेर चलते थे, एक वैध और दूसरा अवैध। यह सब करके कांग्रेस की भूपेश सरकार सरकारी खजाने तक को लूटकर गई। अब भारतीय जनता

पार्टी चाहती है कि सबकुछ वैध हो, पारदर्शी हो, ऑनलाइन हो और किसी भी प्रकार से राजस्व की हानि न हो। इस नेक इरादे से शुरू किए गए एप पर बघेल आज प्रलाप कर रहे हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि जब कोरोना की भयावह त्रासदी से पूरा प्रदेश जूझ रहा था तब मुख्यमंत्री रहते हुए बघेल शराब की बिक्री चालू कराने के लिए किस स्तर तक जाकर लालायित हो रहे थे! जब एक तरफ कोरोना के चलते

लोग मर रहे थे और जब जनता को दुआ और दवा की जरूरत थी, तब तो खुद बघेल भी एप लॉन्च करके घरों-घर शराब पहुँचा रहे थे और जो लोग बघेल के कहने पर यह काम कर रहे थे, आज सब जेल में हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि गंगाजल की सौगंध खाकर किए गए पूर्ण शराबबंदी के वादे से मुकरने और 2 हजार करोड़ रूपए का शराब घोटाला करने वाले बघेल आज किस मुँह से एप की लॉन्चिंग तानाकशी

कर रहे हैं? कम-से-कम बघेल को तो ऐसी ओछी टिप्पणियाँ करना शोभा नहीं देता। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश की भाजपा सरकार के हर काम में प्रगतिशिलता है। बघेल ने तो शराब की कोचियागिरी की सनक में प्रदेश की युवा प्रतिभाओं की बेरोजगारी का नजाम उड़ाकर उन्हें रोजगार के नाम पर शराब के गोरखधंधे में डिलीवरी ब्यॉय तक बनाने का कर्त्तविकृत कृत्य करने में शर्म तक महसूस नहीं की थी।

आज सुबह मुख्यमंत्री के कॉल ने निशा के लिये खोली किलिमंजारो फतह की राह

रायपुर। अलसुबह आज बिलासपुर में रहने वाली निशा यादव के पास एक फोन आया और फोन पर एक सौम्य सी आवाज में किसी ने उससे कहा आपको किलिमंजारो चढ़ना है, आप खर्च की चिंता न करें। निशा चकित हुई और आश्चर्य से पूछा आप कौन हैं, सामने से आवाज आई बेटा मैं विष्णु देव साय बोल रहा हूँ।

निशा ने आश्चर्यचकित भाव से कहा आप सच में मुख्यमंत्री में बोल रहे हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने पूरी बात बताई और कहा कि आप अपने लक्ष्य पर फोकस करें। छत्तीसगढ़ के हर एक बेटे का सपना पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री के स्नेहपूर्ण आश्रयन को सुनकर निशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। निशा को इस बात पर भी यकीन करना पड़ा मुश्किल हो रहा था कि बिना किसी आवेदन या आग्रह के मुख्यमंत्री ने उनका सपना पूरा करने की पहल की है। मुख्यमंत्री साय ने निशा के साथ पर्वतारोहण के बारे विस्तार से बात की। निशा ने मुख्यमंत्री को यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी माउंट एलब्रस की चढ़ाई के दौरान



आई चुनौतियों के बारे में बताया। उसने बताया कि पर्वत की यात्राएं रोमांच से भर देती हैं। पर्वतों की चोटी पर तिरंगा फहराना गर्व से भर देता है। निशा ने आगे बताया कि अब अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी किलिमंजारो को फतह करना चाहती हैं और उनका अंतिम लक्ष्य माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने का है। निशा ने नम आवाज में मुख्यमंत्री को आगे बताया कि मैं पिछले कई दिनों से सो नहीं पा रही थी। मेरे पिता आँटो चालक हैं और मेरे सपने को पूरा कर पाना उनके लिए कठिन था। मन में बड़ी दुविधा थी कि यह कैसे संभव हो पाएगा, मेरा सपना कैसे पूरा होगा। आज आप ने मेरी सारी चिंताओं को दूर कर दिया है। मुख्यमंत्री जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। निशा की आत्मविश्वास भरी इन बातों को सुनकर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अपनी बेटियों पर गर्व है। हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ की बेटे माउंट एवरेस्ट पर भी तिरंगा फहराए। उन्होंने कहा कि आर्थिक हालात से हौसले परत नहीं होते। उन्होंने निशा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपका आत्मविश्वास और जुनून जरूर आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाएगी।

अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का हुआ समापन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में दो दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस एवं अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में विभिन्न राज्यों के लोक नर्तक दलों ने अपनी-अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों में उत्साह भर दिया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड समेत छत्तीसगढ़ के जनजातीय एवं लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी। त्रिपुरा से आए बु रियांग जनजाति समुदाय के नर्तक दल ने परंपरागत लोकनृत्य होजागिरी की प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस नृत्य में ब्रू रियांग जनजाति समुदाय की युवतियों ने सिर के ऊपर बोटल को संभालते हुए अद्भुत सामंजस्य के साथ प्रस्तुति दी। नृत्य के दौरान नर्तकों के कलात्मक प्रदर्शन को भी दर्शकों की खूब सराहना मिली। इसके पूर्व हिमाचल प्रदेश के लोक कलाकारों ने मन्मोहक कार्यांग नृत्य प्रस्तुति दी, जो हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। इस नृत्य में नर्तक दल एक दूसरे की भुजाओं को चुनकर माला जैसा पैटर्न बनाया, धीरे-धीरे कदमताल करते हुए प्रतीकात्मक रूप से माला की मोती जैसे बिखरते हुए फिर जुड़ते हुए पारंपरिक कपड़े पहने और गहनों से सुसज्जित नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद मेघालय के गारो नृत्य की प्रस्तुति हुई। गारो समुदाय के लोग इस नृत्य में फसल कटाई के बाद देवता मिस्सी सालजोंग की आराधना कर उन्हें धन, धान्य के लिए अपनी आस्था और निष्ठा व्यक्त करते हैं।



मोदी ने 6600 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर देश के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं विस्तार वाली 6600 करोड़ की लागत वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के जनजातीय इलाकों और जनजाति समुदाय के कल्याण के लिए पांच गुना बजट खर्च कर रहे हैं। दस साल पहले इसका बजट मात्र 25,000 करोड़ रूपए हुआ करता था, जो अब बढ़कर 1,25,000 करोड़ रूपए हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बिहार के जमुई में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती वर्ष के शुभारंभ समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। जमुई में आयोजित इस कार्यक्रम का लाईव प्रसारण पूरे देश में हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने इतिहास के एक बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास किया है।

उप मुख्यमंत्री साव ने किया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के हितग्राही सर्वेक्षण का प्रदेशव्यापी शुभारंभ

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत हितग्राही सर्वेक्षण कार्य आज से शुरू हो गया है। इसके तहत प्रदेश के शहरी आवासहीनों का स्वयं का पक्का आवास मिलेगा। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने जिला मुख्यालय मुंगेरी स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल दाऊपारा मुंगेरी में प्रदेशव्यापी सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने जिला मुख्यालय मुंगेरी के वार्ड क्रमांक 16 में धनु निर्मलकर और सुजीत पतरस के घर पहुंचकर हितग्राही सर्वेक्षण किया और पीएम आवास के लिए उनका फार्म भरवाया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया।

प्रमुख समाचार

प्रदेश में अपराधिक घटनाओं के साथ डिजिटल अपराध से भय का माहौल

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद अपराधियों के हौसले बढ़े हैं। प्रदेश में अपराधिक घटनाओं के साथ डिजिटल अपराध से भय का माहौल है। आम जनता, घर, बाहर, बाजार, स्कूल, ऑफिस में असुरक्षित महसूस कर ही रही है अब अपराधी डिजिटल माध्यम से भी अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। राजधानी में चार दिन के भीतर तीन बड़े डिजिटल अपराध हुए हैं। पंडरी, देवेन्द्र नगर, गंज थाना क्षेत्र में एलआईसी अफसर, डाक्टर सहित सभ्रत लोगों को अपना शिकार बनाया। अपराधी बैंकॉफ होकर नकली वर्दी पहनकर विडियो काल करके खुलेआम जनता को ठग रहे हैं। शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का सपना दिखाकर लूट रहे हैं। कर्मचारियों के भविष्य निधि का फंड तक इस सरकार में सुरक्षित नहीं रहा है। पूरे प्रदेश में इसी तरह की घटना लगातार हो रहा है। फर्जी सुप्रीम कोर्ट बनाकर सुनवाई की जा रही है। कोई खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई, इंकम टैक्स अधिकारी, ईडी अधिकारी, कन्स्टम अधिकारी, मुंबई क्राईम ब्रांच के अधिकारी बताकर डिजिटल माध्यम से जनता को डराकर पैसा लूट रहे हैं। जिसे रोकने में भाजपा की सरकार असफल रही है।

फिर से ट्रेनों को रद्द किये जाने का कांग्रेस विरोध करती है

रायपुर। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 49 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया जाना जनता के ऊपर अत्याचार है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुकला ने कहा कि बार-बार ट्रेनों को रद्द किये जाने का कांग्रेस विरोध करती है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली यात्री ट्रेनों को पिछले चार सालों से अचानक रद्द करने का सिलसिला चल पड़ा है। वर्तमान में भी पहले 16 एक्सप्रेस, 5 लोकल एवं फिर 24 ट्रेनों को एक बार फिर से रद्द कर दिया गया है। रेलवे का यह कदम बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों को रद्द किया जाना रेल यात्रियों के ऊपर अत्याचार है। रेलवे को यदि मेंटेनेंस करना था तो इसके लिये काम की समय सारणी का ऐसा प्रबंध किया जाना चाहिये जिससे यात्री सुविधाएं बाधित न हो। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुकला ने कहा कि पिछले चार वर्षों से देश की रेल सुविधाएं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। यात्री ट्रेनों की बिना कारण बताये रद्द कर दिए जाने का फरमान जारी कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली सैकड़ों यात्री ट्रेनों को अनेकों बार महीनों तक के लिए रद्द किया गया है। महीने पहले यात्रा की योजना बना कर रिजर्वेशन करवाने वाले यात्री रेलवे की इस मनमानी से परेशान होते हैं।

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था बर्दाहल जांच

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने छत्तीसगढ़ में बर्दाहल हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की स्थिति चिंताजनक हो चुकी है। डायलिसिस, कीमोथेरेपी, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी मशीनें बंद पड़ी हैं। टेस्ट किट बिना उपयोग के एक्सपायरी हो रहे हैं। टीकाकरण कार्यक्रम तक बाधित है, टीके सप्लाई के दौरान टेंपरेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं जिसके चलते बिलासपुर और अंबिकापुर में शिशुओं की मौतें हुईं। शुगर, थायरॉइड तक की जांच तक बंद है, रिएजेंट की कमी के चलते राजधानी रायपुर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में 6 माह से हार्ट का ऑपरेशन बंद है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा की सरकार 11 महीने के भीतर ही छत्तीसगढ़ की जनता के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों का भी भरोसा खो चुकी है। साय सरकार की अकर्मण्यता के चलते सरकारी डॉक्टर अपने पद से त्यागपत्र की पेशकश कर रहे हैं। हर माह सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मी रिटायर हो रहे हैं लेकिन यह सरकार एक भी पद पर नियमित भर्ती नहीं कर पा रही है।

सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहा छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का विमोचन किया। इसके साथ ही सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 पूरे दिन ट्रेंडिंग करता रहा। एक्स हैंडल पर पहले नंबर था। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नयी औद्योगिक नीति बनाने की घोषणा की थी। इसे अमलीजामा पहनाने हुए राय गठन के 25वें वर्ष यानी रजत जयंती के साथ ही जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 14 नवंबर को नयी छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 पर विमोचन किया। विमोचन के बाद श्री साय ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि इस औद्योगिक नीति का निर्माण सभी की सहभागिता से किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद यह 6वीं औद्योगिक नीति है जिसमें प्रदेश के युवाओं को अधिक-से-अधिक रोजगार, पर्यटन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में भी उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नयी नीति से अग्निवीरों, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए भी रोजगार और स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होगा। नयी औद्योगिक विकास नीति में पर्यावरण संरक्षण का भी समुचित प्रावधान किया गया है।

गुरुनानक देव जी ने दिया समतामूलक समाज के निर्माण पर जोर-साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के खालसा स्कूल प्रांगण में गुरुनानक जयंती के अवसर पर आयोजित प्रकाश पर्व में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने कीर्तन दरबार में मत्था टेका और सभी छत्तीसगढ़ वासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने प्रकाश पर्व पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि आज इस पवित्र दिन सिख समुदाय के अपने भाइयों-बहनों के बीच आकर मैं बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। गुरु नानक देव जी का जीवन न केवल सिख समुदाय के लिए प्रेरक है अपितु सभी भारतीयों के लिए उनका जीवन प्रेरणादायी है। गुरु नानक जी के वचनों में सामाजिक एकता पर जोर दिया गया है। उन्होंने एक समतामूलक समाज के निर्माण पर जोर दिया। देश को आज़ादी में सिख समाज का बहुत बड़ा योगदान है। सिख समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली और समृद्ध है। धर्म के प्रति समर्पण और सेवा की भावना सिख समाज की अभिन्न पहचान है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जब हम गुरु गोविंदसिंह जी का जीवन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके पुत्र साहेबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी पर धर्म बदलने का दबाव आया।

भाजपा बताये छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी कब लागू होगी? - दीपक बैज

शराब की काली कमाई के मोह में भाजपा सरकार रेस्टोरेंट, ढाबों में शराब बिकवायेगी - कांग्रेस

रायपुर। भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश के रेस्टोरेंट और ढाबों में शराब परोसे जाने के निर्णय का कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार शराब के ब्रांड की उपलब्धता के लिये एप बनाई है। सरकारी दफ्तर में काम काज की मानिटैरिंग का कोई एप नहीं है लेकिन शराब की ब्रांड के लिये सरकार ने एप बना लिया है। भाजपा सरकार शराब की काली कमाई के लिये प्रदेश में शराब की खपत बढ़ाने में लगी है। विपक्ष में रहते शराबबंदी को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करने वाले भाजपाई अब शराब बिक्री के पैरोकार बन गये हैं। शराब बंदी को लेकर पांच सालों तक हल्ला

मचाने वाले भाजपाई बतायें शराबबंदी कब होगी? भाजपा के हर छोटे बड़े नेता ने जनता के बीच घूम-घूम कर शराबबंदी के लिये बहु चढ़कर बातें किया था। सरकार में आने के बाद सरकार और भाजपाईयों दोनों के जुवान पर ताला लग गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पहले एयर कूल्ड आहाते बनाकर शराब बिक्री को बढ़ावा दिया गया। आहाते आबंटन में बड़ा घोटाला साय सरकार ने किया है। आहातों के नाम पर सरकार शराब की काली कमाई में लगी हुई है। पूरे प्रदेश

में कुछ लोगों को चिन्हांकित कर आहाते आवंटित किये गये हैं। प्रभावशाली भाजपा नेताओं के अनुशंसा पर आहाते आवंटित किये गये हैं। भाजपा सरकार के राज में शराब की कोचियागिरी शुरू हो गयी है। मुंगेरी और राजनांदगांव में सरकार के इशारे पर अंधेध वसूली के लिये दबाव बनाते आबकारी निरीक्षकों के वीडियो को प्रदेश की जनता ने देखा है। प्रदेश के अनेकों स्थानों से खबरे आई है कि शराब दुकानों से 200 रु. प्रति पेट्टी अतिरिक्त देकर कोचिये गली, मोहल्ले में शराब बेच रहे हैं और इनको पूरा

सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य में शराब के नाम पर वसूली की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। दुकानों में कौन सी शराब बिकेगी, कौन से निर्माता के ब्रांड राज्य में बिकेगा, इसके नाम पर कमीशन खेल बड़े पैमाने पर हो रहा है। शराब के इस सुनियोजित घोटाले में उच्च स्तर के लोग संलिप्त है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार कमीशनखोरी के लालच में बार-बार शराब खरीदी के नियमों में बदलाव कर रही है। एफएल-10 का लाइसेंस निरस्त कर सरकार द्वारा सीधे उत्पादक कंपनियों से

शराब इसलिये खरीदने का फैसला लिया गया है ताकि कंपनियों से मोटा कमीशन वसूला जाय। सरकार ने 12 कंपनियों को एफएल-10 का लाइसेंस दिया तथा उनके साथ एक वर्ष तक सप्लाई का एग्रीमेंट किया गया उनसे बांड भी भरवाया गया इसके बाद 10 कंपनियों को एफ एल-बी का लाइसेंस दिया गया उनसे भी एग्रीमेंट किया गया फिर अचानक सरकार ने इन कंपनियों से किये एग्रीमेंट को कमीशनखोरी के लिये रद्द कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 100 से अधिक शराब दुकानो को बंद किया था।

रायपुर। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से रायपुर में दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 13 और 14 नवंबर को आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण आवास के प्रभावी कार्यान्वयन और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के ग्रामीण आवास के उप महानिदेशक गया प्रसाद, ग्रामीण आवास निदेशक शक्तिकांत सिंह, एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) के निदेशक शैलेश कुमार, संयुक्त निदेशक आशीष शिंदे और आईटी के

संयुक्त निदेशक अजय मोरे शामिल थे। उपस्थित अधिकारियों ने ग्रामीण आवास परियोजनाओं में नवाचार और सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। 113 नवंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कार्यशाला का शुभारंभ हुआ, जहां विशेषज्ञों और अधिकारियों ने ग्रामीण आवास में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, समन्वय मॉडलों और तकनीकी समाधानों पर गहन विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक सिंह, संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना रजत बंसल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सहयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की। इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के